राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण रविवार,७मार्च २०२१ वर्ष-४, अंक -४३ पृष्ठ-०८ मूल्य-०१रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

तेज हुई टीकाकरण की रफ्तार, एक दिन में लगाई गई रिकॉर्ड 13.88 लाख डोज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीका लगवाने और निजी अस्पतालों को शामिल करने के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को रिकॉर्ड लगभग 14 लाख टीके लगाए गए। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। अब तक कोरोना वैक्सीन की 1.8 करोड़ डोज दी जा चुकी है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इन लोगों को लगा टीका

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1.8 करोड़ डोज लेने वाले लाभार्थियों में स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल से अधिक उम्र के लोग और गंभीर रोग से ग्रसित 45 साल से ज्यादा आयु के व्यक्ति शामिल हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी टीका लगवाया। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 68,53,083 स्वास्थ्यकर्मियों को पहली और इनमें से 31,41,371 को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसी तरह फ्रंटलाइन वर्कर्स में पहली डोज लेने वाले 60,90,931 और इनमें से दूसरी डोज लेने वाले 67,297 लाभार्थी शामिल हैं। एक मार्च के बाद से गंभीर रोगों से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा उम्र के 2,35,901 और 60 साल से अधिक आयु के 16,16,920 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के 48वें दिन गुरुवार को रिकॉर्ड 13,88,170 डोज दी गई। लाभार्थियों को एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार कोरोना की खुराक की गई है। इनमें 10,56,808 लाभार्थियों को पहली और 3,31,362 लाभार्थियों को दूसरी डोज दी गई। 10,56,808 लाभार्थियों में सबसे ज्यादा संख्या 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की 6,15,903 रही। जबकि, गंभीर रोगों से ग्रस्त 45 से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों की संख्या 92,109 थीं।

महाराष्ट्र में लॉकडाउन के लिए मजबूर होंगे उद्धव ठाकरे?

सिर्फ 6 दिन में मिले 50,000 से ज्यादा केस

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोरोना के कहर ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सिर्फ 6 दिनों के भीतर राज्य में 50 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में लोगों को डर है कि राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर कहा था कि वह इसे थोपना नहीं चाहते, मजबूरी भी कोई चीज है। जिसके बाद से महाराष्ट्र में लगातार मामलों में उछाल देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते में 1 मार्च को छोड़कर राज्य में औसतन 7 हजार मामले दर्ज किए गए हैं। 1 मार्च को 6,397 नए मामले दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर, 28 फरवरी और 5 मार्च के बीच, महाराष्ट्र में 51,612 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। 28 फरवरी को, महाराष्ट्र में दैनिक संक्रमण की संख्या 8,283 थी। एक मार्च को संख्या कम होकर 6,397 हुई और बाद में 2 मार्च को फिर 7,863 पर पहुंच गई। 3 मार्च को कुल 9,855 नए मामले सामने आए और 4 मार्च को यह संख्या 8,998 थी। 5 मार्च को, राज्य में 17 अक्टूबर, 2020 के बाद से सबसे ज्यादा दैनिक मामले आने की सूचना दी गई, जब राज्य में 10,259 मामलों का उछाल दर्ज किया गया था।

मुंबई भी इन बढ़ते मामलों में लगातार भागीदार रही है, यहैं दैनिक रूप से शहर में हर रोज कोरोना के 900 मामले देखने को मिल रहे हैं।

जिलों में लॉकडाउन

अमरावती जैसे जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। पिछले लॉकडाउन के अधिकतर प्रतिबंध 8 फरवरी तक थे, जिले में स्कूल और शैक्षिक संस्थान अभी बंद हैं। अमरावली उन जिलों में से हैं जहां लगातार बढ़ते मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

8 से 15 दिनों की डेडलाइन

21 फरवरी को एक प्रेस मीटिंग को संबोधित करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आठ से 15 दिनों में स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तब तक, राज्य में किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा को प्रतिबंधित करने के अलावा कोई राज्यव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

लॉकडाउन को लेकर क्या कहते हैं मंत्री?

- नेशनल लॉकडाउन के एक साल बाद लोगों के कामकाज और प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाना संगत नहीं लगता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में एक और लॉकडाउन करने की अनिच्छा व्यक्त की थी, उन्होंने 28 फरवरी को कहा कि 'मैं इसे थोपना नहीं चाहता, लेकिन 'मजबूरी' भी कोई चीज है।' इसके बाद से महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं।

महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पिछले हफ्ते कहा था कि राज्य सरकार मुंबई लोकल टाइमिंग पर फिर से प्रतिबंधित लगाने पर विचार करेगी, मुंबई लोकल की सेवाओं को 1 फरवरी को जनता के लिए खोल दिया गया था।

बृहन्मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि नागरिक निकाय मुंबई के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बना रहा है क्योंकि यह अभी परीक्षण और निगरानी बढ़ाने पर निर्भर है।

- सिर्फ 6 दिनों के भीतर राज्य में 50 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में लोगों को डर है कि राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर कहा था कि वह इसे थोपना नहीं चाहते, मजबूरी भी कोई चीज है। जिसके बाद से महाराष्ट्र में लगातार मामलों में उछाल देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते में 1 मार्च को छोड़कर राज्य में औसतन 7 हजार मामले दर्ज किए गए हैं। 1 मार्च को 6,397 नए मामले दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर, 28 फरवरी और 5 मार्च के बीच, महाराष्ट्र में 51,612 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। 28 फरवरी को, महाराष्ट्र में दैनिक संक्रमण की संख्या 8,283 थी।

दहेज प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- बेरहम आदमी रहम के लायक नहीं

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति की अग्रिम जमानत यह कहते हुए खारिज कर दी कि बेरहम आदमी रहम के लायक नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस केस में पति का केस मजबूत था और उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। हालांकि, सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में पूरी तरह से महिला के आरोपों का समर्थन किया।

खबर के मुताबिक, पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने उससे अलग रहते हुए किसी अन्य आदमी को अपनी नग्न तस्वीरें भेजी थीं। इसको लेकर की गई पुलिस शिकायत के बाद जवाब में पत्नी ने उसपर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पति के वकील ने कहा कि महिला जब अपने पति से अलग रह रही थी तो उस दौरान उसने दूसरे शख्स के साथ सैकड़ों नग्न तस्वीरें भेजीं। इसके बाद उसने दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया जबकि दहेज के तौर पर एक भी रुपया न तो लिया गया था और न ही मांगा गया था। वकील ने कहा कि महिला का आरोप एक तरफ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पति की अग्रिम जमानत की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी, 'अगर महिला ने किसी और के साथ नग्न तस्वीरें शेयर की तो आप उन्हें तलाक दे सकते हैं लेकिन

आप उनके साथ क्रूर नहीं हो सकते।' कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर में आरोप हमेशा एकतरफा ही होते हैं। ऐसी कोई एफआईआर नहीं होती जिसे आरोपी और शिकायतकर्ता साथ में दर्ज करवाएं। मामले में अब पति को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि राजस्थान कोर्ट से आरोपी शख्स के माता-पिता को अग्रिम जमानत मिल गई है।

पत्नी-बच्चे ही नहीं, माता-पिता भी बेटे की कमाई के हिस्सेदार - कोर्ट

नई दिल्ली। गुजाराभत्ते के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की कमाई पर सिर्फ उसकी पत्नी या बच्चों का हक नहीं होता है, बल्कि बुजुर्ग माता-पिता भी उसकी आय के हिस्सेदार होते हैं। इस तरह अदालत ने साफ किया कि पत्नी व बेटे के बराबर ही किसी भी व्यक्ति पर उसके माता-पिता का अधिकार होता है। तीस हजारी स्थित प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीष कथपालिया की अदालत ने इस मामले में वादी महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी पति से आय संबंधी हलफनामा पेश करने को कहा था। महिला का कहना था कि उसके पति की मासिक आय 50 हजार रुपये से ज्यादा है। जबकि उसे व उसके बच्चे को महज दस हजार रुपये गुजाराभत्ता दिया जा रहा है। पति द्वारा पेश हलफनामे में कहा गया कि उसकी मासिक आय 37 हजार रुपये है और इसी रकम में से पत्नी व दो साल के बेटे की परवरिश के अलावा खुद का खर्च और बुजुर्ग माता-पिता की गुजर-बसर भी करनी होती है।

अदालत ने सुरक्षा अधिकारी से तलब की रिपोर्ट-अदालत ने पति के हलफनामे के बाबत सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट पेश करने को कहा था। अधिकारी ने रिपोर्ट में बताया कि प्रतिवादी ने सही तथ्य पेश किए हैं। उसका आयकर खाते के मुताबिक, उसकी मासिक आय 37 हजार रुपये ही है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि माता-पिता के जीवन-यापन के अलावा उनकी बीमारी का खर्च भी प्रतिवादी ही उठाता है। अदालत ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया। हालांकि पत्नी का कहना था कि पति की ज्यादा जिम्मेदारी उसके व उसके बच्चे के प्रति ही बनती है। इसलिए उसका गुजाराभत्ता बढ़वाया जाए।

अदालत ने छह हिस्सों में बांटी तनख्वाह-अदालत ने इस मामले का निपटारा करते हुए प्रतिवादी पति की तनख्वाह को छह हिस्सों में बांटा। दो हिस्से प्रतिवादी को दिए। इसके अलावा पत्नी, बेटे, माता व पिता को एक-एक हिस्सा दिया। अदालत ने इस मामले में पत्नी की पति की आय के हिसाब से गुजाराभत्ता बढ़ाने की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्णय किया है। अदालत ने कहा कि पत्नी व बेटे का हिस्सा 12 हजार पांच सौ रुपये बैठता है। इसलिए पति को अब प्रतिमाह की दस तारीख को अपनी पत्नी व बेटे को गुजाराभत्ता रकम का भुगतान करना है।

फैमिली केक की तरह होती है परिवार की आय

अदालत ने अपने निर्णय को एक उदाहरण की तरह पेश करते हुए कहा कि परिवार के कमाने वाले सदस्य की मासिक आय एक फैमिली केक की तरह होती है। जिसे बराबर हिस्से में बांटकर खाया जाता है। इसी तरह आय का भी बंटवारा होता है।

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं...!

नई दिल्ली। विजय माल्या को भारत कब लाया जाएगा? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। ब्रिटेन ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत में वांछित भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल मई में केस हार चुका है। उसकी मनी लांड्रिंग मामले में भी भारत को तलाश है। यह पूछे जाने पर माल्या को कब प्रत्यर्पित किया जाएगा और क्या इस मामले में अभी कोई कानूनी मसला लंबित है, भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने किसी केस का नाम लिए बिना कहा कि वह भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपितों को भारत लाने की तात्कालिकता, महत्व और इच्छा को समझते हैं। उन्होंने कहा प्रत्यर्पण का मामला प्रशासनिक के साथ ही कानूनी भी है और यह अदालत में है। माल्या मामले में प्रशासन की तरफ से जो कुछ भी किया जाना था, उसे गृह मंत्री ने कर दिया है। अब यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें अब जो भी करना है वह जजों को ही करना है। गौरतलब है कि विजय माल्या जमानत पर ब्रिटेन में हैं। माल्?या पर 17 भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। माल्य 2 मार्च, 2016 को भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। भारतीय एजेंसियों ने ब्रिटेन की अदालत से माल्या के प्रत्यर्पण की अपील की थी। लंबी लड़ाई केा बद ब्रिटेन की अदालत ने 14 मई को माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अपील पर मुहर लगा दी थी। हालांकि, कानून दांवपेच के चलते उसे अब तक भारत नहीं लाया जा सकता है।

बिहार में पटना का तापमान पहुंचा 33 डिग्री तक, 15 मार्च तक राहत के नहीं आसार

पटना। बिहार में एक हफ्ते तक राहत के बाद गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी जिलों के पारे में एक से डेढ़ डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का असर न्यूनतम पारे पर भी पड़ा है। पटना में शुक्रवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और अधिकतम पारा 33.8 डिग्री दर्ज किया गया।

राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पटना में ही दर्ज किया गया। गर्मी की वजह से दोपहर में सड़कों पर आम दिनों से कम लोग दिखे। पिछले 24 घंटों में ढाई डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी का असर

राजधानी के बाजारों पर भी दिखा है। गया, भागलपुर और पूणिया में भी पारे में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार शुष्क पछुआ हवा बढ़ने से वातावरण में नमी की कमी होती जा रही है और आर्द्रता का प्रतिशत नीचे आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 मार्च तक 32 से 34 डिग्री के बीच पारा रहने का अनुमान है।

मार्च से मई तक प्री मानसून सीजन, कालबैशाखी का रहेगा प्रभाव

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मार्च से मई तक सूबे में प्री मानसून सीजन माना जाता है। इस दौरान सूबे में हर साल कालबैशाखी प्रभावी हो जाता है। इसमें तेज मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। राज्य में हर साल इस मौसम में ओला वृष्टि भी होती है। मौसम विभाग की ओर से ऐसे में पूर्वानुमान को बेहतर करने के उद्देश्य से अभी से तैयारी शुरू हो गई है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में इसकी स्थिति आ सकती है। धूल भरी आंधी का प्रभाव राज्य के कई हिस्सों में दिखेगा। सात मार्च से सूबे में पूर्वा के बहने के संकेत मिल रहे हैं। इसके प्रभाव से न्यूनतम पारा आंशिक रूप से ऊपर चढ़ेगा, जबकि राज्य के दक्षिणी भाग में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है।

ऐसा रहा प्रमुख शहरों का पारा

शहर	अधिकतम	न्यूनतम
पटना	33.8	15
गया	32	11.7
भागलपुर	32.5	16.5
पूर्णिया	29	14.2

मुंगेर में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदला

मुंगेर। बिहार के मुंगेर जिले में 12 कट्ठा 3 धूर जमीन के लिए दो पक्षों में जारी अदावत खूनी संघर्ष में बदल गई। और तीन लोगों को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। इस खूनी संघर्ष की शुरुआत शुक्रवार की दोपहर हो गई थी जब दोनों पक्ष के बीच मारपीट के बाद तनाव का माहौल बन गया। इसके बाद रात आठ बजे दोनों पक्ष के बीच अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। घटना जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मोकबिरा चांय टोला की है। दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। इसमें दोनों पक्षों के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक पक्ष से जयजय राम साव व उसका पुत्र कुंदन साव और दूसरे पक्ष से सागर कुमार महतो शामिल है। करीब दो घंटे तक गोलीबारी के बाद चार थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष से आर्मी जवान चंदन साव को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद विराट टोला में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जबकि ग्रामीण दहशत में हैं।

जमीन को लेकर कई वर्षों से चल रहा विवाद

जानकारी के अनुसार 12 वर्ष पूर्व ओम प्रकाश सहनी ने 12 कट्ठा 3 धूर जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर कब्जा को लेकर रामा बिंद ने ओमप्रकाश से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी थी। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही थी। इसी विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। रात आठ बजे दोनों पक्ष के बीच अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। इसमें 26 वर्षीय कुंदन साह गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि गोलीबारी के दौरान घटनास्थल पर ही 18 वर्षीय सागर बिंद और 55 वर्षीय जयजय राम साह की मौत हो गई। सदर अस्पताल में रात 11:30 बजे तक दो लोगों का ही शव पहुंचा था। जिसमें सागर बिंद और कुंदन साव का शव शामिल है। जबकि जयजय राम साव का शव देर रात तक अस्पताल नहीं पहुंचाया। इस बारे में मुंगेर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी के दौरान तीन लोगों की मौत हुई है। एक पक्ष से जयजय राम साह व उनके पुत्र कुंदन साह और दूसरे पक्ष से सागर कुमार महतो की मौत हुई है। पुलिस मामले की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। घटना को लेकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस मामले में एक आर्मी जवान को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।

दो घंटे फायरिंग और तीन की हत्या

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

स्वतंत्रता के मानक

यूं तो पश्चिमी जगत, खासकर अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा सिखाने के अपने मानक निर्धारित करता है। जिसे उसके स्वतंत्र देशों पर दबाव बनाने के तौर-तरीके के रूप में देखा जाता है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद उम्मीद थी कि सरकार और उनके कथित थिंट टैंक भारत के लोकतंत्र, प्रेस की आजादी, इंटरनेट पर रोक व कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत को घेर सकते हैं। दुनिया में कथित रूप से लोकतंत्र की निगहबानी करने वाले अमेरिकी एनजीओ 'फ्रीडम हाउस' ने ताजा रिपोर्ट में यह दलील दी है कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, जिसे उसने आंशिक बताया है। यानी नागरिक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। हालांकि, रिपोर्ट में अन्य देशों में भी लोकतंत्रों की स्थिति को चिंताजनक बताया गया है। इसके बावजूद एक नागरिक के तौर पर हमें यह बात परेशान करने वाली जरूर है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता को आंशिक बताया जा रहा है। हालांकि, खुद अमेरिका की पिछली सरकार में जिस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ायी गईं, उसका जिक्र अमेरिकी थिंक टैंक नहीं करते। ट्रंप शासन में शरणार्थियों के साथ अमानवीय व यवहार, कुछ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक, रंगभेद के संघर्ष तथा मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाया जाना किस लोकतांत्रिक मर्यादा के दायरे में आते हैं? अपने साम्राज्यवाद के विस्तार के लिये किस तरह दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारों को अपदस्थ करने का खेल चला, उसकी पूरी दुनिया गवाह है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल ने अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट को वैचारिक साम्राज्यवाद का नमूना बताया। बहरहाल, देश में सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस रिपोर्ट की अपनी सुविधा से अलग-अलग व्याख्या की जा रही है। इसको लेकर वैचारिक विभाजन साफ नजर आ रहा है। बहरहाल, एक नागरिक के तौर पर हमें भी मंथन करना चाहिए कि क्या वाकई भारतीय लोकतंत्र में एक नागरिक के रूप में हमारी आजादी का अतिक्रमण हुआ है। साथ ही रिपोर्ट में दी गई दलील को भारतीय परिस्थितियों के नजरिये से भी देखने की जरूरत है। दरअसल, इस रिपोर्ट में जिन बिंदुओं को आधार बनाया गया है उनके अन्य पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कहा गया कि कोरोना संकट में देश में बेहद सख्त लॉकडाउन लगाया गया, जिससे लाखों श्रमिकों को मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ा। इस दलील का तार्किक आधार नजर नहीं आता क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में सख्त लॉकडाउन को कोरोना से निपटने का कारगर माध्यम माना गया। लॉकडाउन से जुड़ी लापरवाहियों की बड़ी कीमत अमेरिका ने चुकायी है, जहां अब तक तमाम आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद पांच लाख लोग कोरोना संक्रमण से मौत के मुंह में समा चुके हैं। ऐसे में सख्त लॉकडाउन और श्रमिकों के पलायन के मुद्दे को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि देश में लोकतांत्रिक आजादी कम हुई है। रिपोर्ट का एक बड़ा मुद्दा इंटरनेट पर रोक लगाना है जो अमेरिकी कंपनियों के कारोबार को प्रभावित करता है। कश्मीर में परिस्थितियां और पाक के हस्तक्षेप के चलते सरकार ने इंटरनेट नियंत्रण को अंतिम हथियार माना। वैसे भी स्थितियां सामान्य होने पर वहां फोर-जी सेवा बहाल कर दी गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में प्रतिरोध करने वालों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज करने का मुद्दा भी उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि हिंसा न फैलाने वाले लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मामले न दर्ज किये जायें। इसके अलावा रिपोर्ट में कोरोना काल में अल्पसंख्यकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार, सूचना माध्यमों के खिलाफ सख्ती, लव जिहाद व सीएए के दौरान हिंसा के मुद्दों को आधार बनाया गया है। एक नागरिक के तौर पर भी हमारे लिये मंथन का समय है कि क्या हम अपनी स्वतंत्रता पर आंच महसूस करते हैं। रिपोर्ट को सिरे से खारिज करने के बजाय इसका लोकतांत्रिक आधार पर मूल्यांकन करने की जरूरत है। साथ ही व्यवस्था का न्यायपूर्ण बने रहना प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये अपरिहार्य शर्त भी है।

करनी से रेखांकित हो राजनीतिक संवेदनशीलता

विश्वनाथ सचदेव

जब देश का प्रधानमंत्री किसी अस्पताल में पहुंचे टीका लगवाने के लिए तो वातावरण में तनाव दिखना स्वाभाविक है। शायद इसी तनाव को हल्का करने के लिए प्रधानमंत्री ने टीका लगाने के लिए काम में ली जा रही लंबी सूई को देखकर टिप्पणी की होगी। जब नर्स वह इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी तो प्रधानमंत्री ने पूछा-ऐसी सूई तो शायद जानवरों के डाक्टर काम में लेते हैं? नर्स को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। तब प्रधानमंत्री ने कुछ मुस्कराते हुए कहा था, वे सोच रहे थे शायद अस्पताल वाले जानवरों को लगाने वाली सूई इस्तेमाल करेंगे 'क्योंकि राजनेताओं को भी मोटी चमड़ी वाला माना जाता है।' इस पर तो वातावरण का तनाव कम होना ही था। हंसते-मुस्कराते कब टीका लग गया, पता ही नहीं चला। फिर, सुना है, प्रधानमंत्री आधा घंटा अस्पताल में रहे थे, यह देखने के लिए कि टीके का कोई विपरीत असर तो नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उम्मीद भी यही थी। इस आधे घंटे में प्रधानमंत्री ने क्या बातें कीं, यह नहीं पता, पर राजनेताओं की मोटी चमड़ी वाली उनकी बात अब भी हवा में गूंज रही है। सच है, राजनेताओं की मोटी चमड़ी के उदाहरण खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर तरफ बिखरे पड़े हैं ऐसे उदाहरण। इस मोटी चमड़ी के कई मतलब होते हैं, जैसे यह बात कि राजनेताओं के बारे में भले ही कुछ भी कहा जाता रहे, दिखाते वे यही हैं कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे, शायद, फर्क पड़ता भी नहीं है, अन्यथा हमारे नेता अपनी वाणी और व्यवहार, दोनों, पर अंकुश लगाने की आवश्यकता और महत्ता को अवश्य समझते। पर आये दिन दिखने वाले उदाहरणों को देख कर यह सहज ही कहा जा सकता है कि ऐसी कोई चिंता हमारे राजनेताओं को नहीं है। वे यह मानकर चलते हैं कि या तो देश की जनता कुछ समझती नहीं, या फिर उसके समझने से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम भले ही यह कहते रहें कि 'यह पब्लिक है, सब जानती है' और समय आने पर सबक भी सिखा सकती है, पर हमारे राजनेताओं को तो, निश्चित ही, यह लगता है कि जनता कुछ भी कहती-करती रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मोटी चमड़ी इसी को कहते हैं। नेताओं के संबंध में आप कुछ भी कहते रहें, वे यह जानते हैं कि उनकी राजनीति चलती रहेगी। इसलिए वे भी कुछ भी करते-कहते रहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। उनकी राजनीति की दुकान चलती रहेगी। यही कारण है कि न तो हमारे राजनेता भ्रष्टाचार के आरोपों से डरते हैं और न ही उन्हें सज़ायाफ्ता होने का ही कोई डर होता है। हमने भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को उंगलियों से जीत का निशान बनाकर जेल जाते हुए देखा है और सज़ा काटकर आने के बाद ज़िंदाबाद के नारों के साथ जेल के दरवाजे से बाहर निकलते भी देखा है। यह सही है कि सारे नेता ऐसे नहीं होते, पर जो ऐसे होते हैं, वे एक मछली की तरह सारे जल को गंदा करने के लिए काफी हैं। मज़े की बात तो यह है कि मोटी चमड़ी वाले राजनेता हर दल में मिल जाते हैं। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि जो राजनेता ज़्यादा मोटी चमड़ी वाला होता है, वह राजनीति के तराजू पर ज़्यादा भारी भी माना जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर होते हैं हमारे राजनेता। समय और अपने स्वार्थ की मांग के अनुसार वे कभी भी अपनी टोपी का रंग बदल सकते हैं, बदल लेते हैं। हर चुनाव के पहले, या वैसे भी, हम इन राजनेताओं को टोपियां बदलते देखते हैं। कल तक वे जिस रंग की टोपी का मज़ाक उड़ाते रहे थे, आज उसी रंग की टोपी पहन कर, वे ताल ठोक कर मैदान में उतर आते हैं। नीति, सिद्धांत, मूल्य, आदर्श कुछ भी आड़े नहीं आता। न उन्हें कल तक के घोषित विरोधी को गले लगाने में कोई संकोच होता है और न ही उन नारों को अपनाने में, जिनकी वे कल तक भर्त्सना कर रहे थे। नेताओं के दलबदल से अब किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता और न ही राजनेताओं को कहीं ऐसा लगता है कि उनके समर्थक क्या कहेंगे। ये समर्थक भले ही कल तक के विरोधियों के साथ जुड़ने में संकोच करें, भले ही उन्हें लगे कि वे क्या मुंह दिखायेंगे, पर दलबदलू राजनेताओं को मुंह दिखाने में कोई शर्म नहीं आती। वे इस बात की भी आवश्यकता नहीं समझते कि अपने किये का कुछ तर्क समझायें। लोग उन्हें लेकर कुछ भी कहते रहें, वे सुनते ही नहीं। न उन्हें अपना कुछ किया ग़लत लगता है, और न ही कुछ कहा हुआ। सच बात तो यह है कि वे यह मान लेते हैं कि कल जो उन्होंने कहा था, वह कल की बात थी, जो बीत गयी सो बात गयी! पर ऐसा होता नहीं है। बीती को बिसार कर आगे की सुधि लेना एक लाभकारी नीति हो सकती है, पर कम से कम राजनेताओं के संदर्भ में ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर हम उनके हाथों में अपना भविष्य सौंपते हैं। उन पर भरोसा करते हैं हम। जनता के इस भरोसे का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। देश के नेताओं को देश की जनता के प्रति जवाबदेह होना ही होगा। उन्हें अपने कहे-किये की जवाबदारी लेनी ही होगी। जनता का यह अधिकार है कि वह जाने कि कल तक किसी एक पार्टी का झंडा उठाने वाला आज दूसरी पार्टी यानी कल तक अछूत समझी जाने वाली पार्टी का दामन कैसे थामने लग गया? और जनता को यह जानने का हक भी है कि हमारे नेता क्यों यह मानकर चलते हैं कि उनके कहे को जनता भूल जाये? प्रधानमंत्री यदि यह कहते हैं कि वे किसी व्यक्ति विशेष को कभी मन से स्वीकार नहीं कर पायेंगे तो उन्हें इस बात का जवाब देना ही होगा कि वह व्यक्ति विशेष उनकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कैसे बन गया? विपक्ष में बैठा कोई राजनेता यदि रातों-रात सत्तारूढ़ दल की अगली पंक्ति में आकर बैठ जाता है तो उसे जनता को यह बताना ही होगा कि कल तक जो वह कह रहा था, वह ग़लत कैसे था? राजनेताओं का मोटी चमड़ी का होना उनके लिए भले ही राजनीतिक सुविधा हो, पर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी संवेदनशीलता ही अंततः उन्हें सही नेता बनाती है। संवेदनहीन राजनीति के लिए जनतांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उस दिन प्रधानमंत्री ने भले ही अस्पताल में वातावरण को हल्का बनाने के लिए मोटी चमड़ी वाली बात कही हो, पर यह मोटी चमड़ी हमारी राजनीति की एक हकीकत है। बदलनी चाहिए यह हकीकत। वास्तव में सब नेता संवेदनहीन नहीं होते, पर ऐसे संवेदनशील नेताओं का ही यह दायित्व बनता है कि वे अपनी कथनी-करनी से राजनीति में संवेदनशीलता की आवश्यकता को रेखांकित करें।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

आज के ट्वीट

तजुर्बा

दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदे का सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है, चंद लम्हों में वो आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं।

- पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ

ज्ञान गंगा

दिमाग

सद्गुरु

हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जीवन ऊर्जा एक खास तरह से व्यवस्थित होती है। आपने देखा होगा कि अलग-अलग लोगों की क्षमता अलग-अलग स्तर की गतिविधियों के लिए अलग-अलग होती है। जब हम कर्म की बात करते हैं तो हमारा मतलब अपने भीतर मौजूद कुछ खास तरह के 'प्रोग्राम' से होता है। ऐसी कई सारी चीजें इस तरह से घटित हुई कि आपके कार्मिक ढांचे ने खुद को एक खास तरीके से सजा लिया। ये कर्म फिलहाल जिस रूप से व्यक्त हो रहा है उसे प्रारब्ध कहते हैं। सिर्फ एक पीढ़ी पहले तक मेरी मां और दादी अपनी रोजमर्रा की बातचीत के दौरान हर तीन से चार वाक्यों में 'कर्म,' 'प्रारब्ध,' 'मुक्ति' या 'मोक्ष' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती रहती थीं। यह सब किसी आध्यात्मिक बातचीत के दौरान नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की आम बातचीत में होता था। क्योंकि तब लोग हमेशा इन चीजों के प्रति जागरूक हुआ करते थे। दरअसल, इस तरह से आप दूसरों को उसी तरह से स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, जैसे वे हैं। क्योंकि जब आप लोगों के करीब रहते हैं तो उनकी कई छोटी-छोटी चीजों पर भी आप बौखला जाते हैं। 'आखिर क्यों यह इंसान इस तरह से व्यवहार कर रहा है?' 'अरे यह तो उसके कर्म हैं।' यानी वह फिलहाल जो भी कर रहा है, वह मजबूर है ऐसा करने को। इसलिए उसके बारे में कोई राय बनाने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल, जिस तरह की आपकी शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक या ऊर्जा की गतिविधियां होती हैं, वह पहले से ही तय होती हैं। तो अब आप उसका बुनियादी रूप बदलना चाहते हैं। इस मामले में यहां ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जो आपको प्रभावित कर रही हैं-आपकी आनुवांशिक (वंश से आई) याददाश्त, कार्मिक याददाश्त, जीवन की कई चीजों का असर व अनुभव जैसे बहुत सारे पहलू हैं। अब आप उन सारी चीजें से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके जीवन को बनाती हैं। अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो यह व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप जीवन की उपयोगिता से परे जाना चाहते हैं, जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपके कर्मों में अभी बदलाव कर सकता हूं, लेकिन अगर आपके भीतर की कोई बुनियादी चीज बदल जाए तो आपका संघर्ष बेहिसाब बढ़ जाएगा।

रसायन मुक्त खिलौनों का उम्मीद भरा बाजार

प्रमोद भार्गव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसायन मुक्त और पर्यावरण हितैषी खिलौने बनाने का आह्वान व्यापारियों से किया है। भारतीय खिलौना मेले में उन्होंने कहा कि अगर देश के खिलौना उत्पादकों को वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ानी है तो उन्हें पर्यावरण-अनुकूल पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। इससे हम आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ दुनिया भर की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। खिलौनों को बच्चों के खेलने की वस्तु भले ही माना जाता हो, लेकिन ये आकर्षित सभी आयु वर्ग के लोगों को करते हैं। बच्चे या किशोर एकाकीपन की गिरफ्त में आकर अवसाद के घेरे में आ रहे हों, तो इस अवसाद को समाप्त करने के लिए खिलौने प्रमुख उपकरण हैं। मूक, बधिर व मंदबुद्धि बच्चों को खिलौनों से ही शिक्षा दी जाती है। स्वस्थ छोटे बच्चों के लिए तो समूचे देश में खेल-विद्यालय अर्थात 'प्ले-स्कूल' खुल गए हैं। साफ है, बच्चों के शैशव से किशोर होने तक खिलौने उनकी परवरिश के साथ, उनके रचनात्मक विकास में भी सहायक हैं। भारत में खिलौना निर्माण का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन में अनेक प्रकार के खिलौने मिले हैं। ये मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु, चमड़ा, कपड़े, मूंज, वन्य जीवों की हड्डियों व सींगों और बहुमूल्य रत्नों से निर्मित हैं। जानवरों की असंख्य प्रतिकृतियां भी खिलौनों के रूप में मिली हैं। खिलौनों की अत्यंत प्राचीन समय से उपलब्धता इस तथ्य का प्रतीक है कि भारत में खिलौना निर्माण लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन था और ये स्थानीय व घरेलू संसाधनों से बनाए जाते थे। नवें दशक में जब कंप्यूटर व डिजिटल क्रांति हुई तो एक बार फिर खिलौनों का रूप परिवर्तन हो गया। अब कंप्यूटर व मोबाइल स्क्रीन पर लाखों प्रकार के डिजिटल खेल अवतरित होने लगे हैं। हालांकि इनमें अनेक खेल ऐसे भी हैं, जो बाल मन में हिंसा और यौन मनोविकार भी पैदा कर रहे हैं। चीन से इनका सबसे ज्यादा आयात होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भारतीय लोक-कथाओं व धार्मिक प्रसंगों पर डिजिटल लघु फिल्में बनाने की बात कही है। यदि खिलौनों के निर्माण में हमारे युवा लग जाएं तो ग्रामीण व कस्बाई स्तर पर हम ज्ञान-परंपरा से विकसित हुए खिलौनों के व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इससे हमारे बच्चे खेल-खेल में भारतीय लोक में उपलब्ध ज्ञान और संस्कृति के महत्व से भी परिचित होंगे। दूसरी तरफ रबर, प्लास्टिक व डिजिटल तकनीक से जुड़े खिलौनों का निर्माण स्टार्टअप के माध्यम से इंजीनियर व प्रबंधन से जुड़े युवा कर सकते हैं। खिलौना उद्योग से जुड़े परंपरागत उद्योगपति अत्यंत प्रतिभाशाली व अनुभवी है, इसलिए वे इस विशाल व्यवसाय में कुछ नवाचार भी कर सकते हैं। कालांतर में ऐसा होता है तो हम एक साथ तीन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। एक चीन के वर्चस्व को चुनौती देते हुए, उससे खिलौनों का आयात कम करते चले जाएंगे। दो, खिलौने निर्माण में कुशल-अकुशल व शिक्षित-अशिक्षित दोनों ही वर्गों से उद्यमी आगे आएंगे, इससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यदि हम उत्तम किस्म के डिजिटल-गेम्स बनाने में सफल होते हैं तो इन्हें दुनिया की विभिन्न भाषाओं में डब करके निर्यात के नए द्वार खुलेंगे। वर्तमान में देश में खिलौनों का बजार 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का है। जिसमें से हम 1.2 अरब डॉलर के खिलौने आयात करते हैं। दरअसल दुनिया में खिलौनों की मांग हर साल औसत करीब पांच फीसदी बढ़ रही है, वहीं भारत में खिलौनों की मांग में 10 से 15 प्रतिशत इजाफे की उम्मीद है। दरअसल भारत में संगठित खिलौना बाजार शुरुआती चरण में है। फन स्कूल इंडिया कंपनी की इस बाजार में प्रमुख भागीदारी है। यह कंपनी विदेशी खिलौनों का वितरण भी भारत में करती है। इनमें हेसब्रो, लोगो, डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, टाकरा-टोमी और रेवेंसबर्ग ब्रांड्स शामिल हैं। फिलहाल भारत में संगठित खिलौना बाजार खुदरा मूल्यों के आधार पर करीब तीन हजार करोड़ रुपए का है। हम भारत में बने परंपरगत रंगों का उपयोग कर फ्लेम रिटार्डेंट जैसे खतरनाक रसायन से बच सकते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) की एक रिपोर्ट ने खिलौनों में जहर की आशंका जताई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अनुसार भारत में आयात होने वाले 66.90 प्रतिशत खिलौने बच्चों के लिए खतरनाक हैं। सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरने के बाद भारत ने फिलहाल चीनी खिलौना कंपनियों के निर्यात पर फिलहाल पाबंदी लगाई हुई है। सरकार को इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को उदार बनाने के साथ प्रशासन की जो बाधाएं पैदा करने की मानसिकता है, उस पर भी अंकुश लगाना होगा।

आज का राशिफल

मेष दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

वृषभ जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। व्यावसायिक तथा आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। धन लाभ की संभावना है। प्रियजन भेंट संभव।

मिथुन पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। किसी मित्र या रिश्तेदार से मिलाप होगा। नेत्र विकार की संभावना है। अपनों से तनाव मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

कर्क जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। खान पान में संयम रखें। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी।

सिंह जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। वाणी की सौम्यता आपके लिए लाभदायी होगी।

कन्या पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। नेत्र विकार की संभावना है। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा।

तुला बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। व्यावसायिक दिशा में किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नए अनुबंध प्राप्त होंगे।

वृश्चिक पारिवारिक जनों के साथ सुखद समय गुजरेगा। पिता या उच्चाधिकारी के कृपापात्र बनेंगे। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। विरोधियों का पराभव होगा। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा।

धनु व्यावसायिक योजनाओं को बल मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

मकर पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आशातीत सफलता मिलेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

कुम्भ जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। विरोधी परास्त होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

मीन आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। वाणी की सौम्यता को बनाये रखना ही हितकर होगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सभी कर्मचारियों, उनके परिजनों को निःशुल्क कोरोना टीका लगवाएगी टीवीएस मोटर कंपनी

बेंगलुरू: दोपहिया और तीन पहिया वाहन निर्माता टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों और उनके नजदीकी परिजनों को निःशुल्क कोरोना टीका लगवाने की शनिवार को घोषणा की। कंपनी ने कहा कि यह टीकाकरण अभियान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इससे देश भर में कंपनी के 35,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्मचारियों को टीके मिलेंगे। टीवीएस मोटर कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष (मानव संसाधन) आर आनंदकृष्णन ने कहा कि कंपनी ने महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न माध्यमों से मदद करने का प्रयास किया है। इस टीकाकरण अभियान के साथ हम अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को प्राथमिकता देने का प्रयास जारी रख रहे हैं।

डीएचएफएल के ऑडिटर ने 1,424 करोड़ रुपए की और धोखाधड़ी पकड़ी

नई दिल्ली: दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. (डीएचएफएल) ने शुक्रवार को कहा कि उसके प्रशासक ने 1,424 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के सिलसिले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई में अतिरिक्त हलफनामा दिया है। कंपनी फिलहाल एनसीएलटी में कॉरपोरेट ऋण समाधान प्रक्रिया में है। 2018 के आईएलएंडएफएस संकट के बाद कंपनी का संचालन प्रशासक द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के प्रशासक ने कंपनी के कामकाज की जांच के लिए ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा गया है कि प्रशासक को लेनदेन आडिटर से शुरुआती रिपोर्ट मिल गई है जिससे पता चलता है कि कुछ लेनदेन का मूल्य कम कर दिखाया गया। ये लेनदेन धोखाधड़ी वाले प्रतीत होते हैं।

रसायन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना लाने पर विचार कर रही है सरकार

नयी दिल्ली, सरकार रसायन क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाने पर विचार कर रही है। इससे घरेलू विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी वी सदानंगद गौड़ा ने शुक्रवार को 'बजट घोषणाओं-2021-22 के क्रियान्वयन की रणनीति' पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश के रसायन एवं पेट्रो रसायन क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने को बातचीत का रुख अपना रही है। वेबिनार का आयोजन फिक्की के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने किया था। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन अकेले सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। ''हमें उद्योग को भरोसे में लेना होगा, जिससे अप्रैल के पहले सप्ताह से क्रियान्वयन शुरू हो सके।''

राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए करदाताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा: सीतारमण

नई दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए घोषित सभी उपायों का वित्त पोषण कर्ज और राजस्व-प्राप्तियों करेगी और इसमें करदाताओं से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। सीतारमण ने शुक्रवार को आईडब्ल्यूपीसी (महिला प्रेस-क्लब) में पत्रकारों से बातचीत में कहा, ''मैं यह उम्मीद नहीं करती कि प्रोत्साहन उपायों का वित्तपोषण करदाताओं द्वारा किया जाएगा। कर्ज दाता से (अतिरिक्त) एक भी रूपया नहीं लिया जाएगा। पूरी राशि राजस्व और कर्ज के रूप में दिखाई गई है। सरकार खर्च करने के लिए उधार ले रही है, लोगों से पैसा नहीं ले रही है। सरकार द्वारा 2020 में कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर पैकेज घोषित किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 13 प्रतिशत से अधिक है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित तरलता (कर्ज के लिए धन) बढ़ाने के उपाया भी शामिल हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन पर विचार कर रही है, सीतारमण ने कहा, ''हमारा इस बारे में रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। इस बारे में जब चीजें पुख्ता होंगी, हम घोषणा करेंगे। लेकिन हम इसपर काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा बलात्कार के आरोपी से यह पूछे जाने पर कि क्या वह बलात्कार के शिकार के साथ विवाह करेगा, पर सीतारमण की राय पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों से निपटने की एक स्थापित व्यवस्था है। जब इस तरह के आरोप आते हैं तो उससे निपटने के स्थापित तरीके होते हैं। मुझे यकीन है कि न्यायालय इस मामले पर ध्यान दे रहा है।

कर के बंटवारे पर निर्णय लेते समय 15वें वित्त आयोग ने निरंतरता, अनुमन्यता को चुना: एनके सिंह

नई दिल्ली: 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने शनिवार को कहा कि आयोग ने करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर निर्णय लेते समय निरंतरता और अनुमन्यता को चुना। इसी कारण कुल पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत बनाए रखा गया है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) द्वारा आयोजित एक वेबिनार में सिंह ने कहा कि इससे पहले प्रत्येक वित्त आयोग ने कुछ हद तक राज्यों के हिस्से की मात्रा में वृद्धि की है, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने कोविड-19 के चलते केंद्र और राज्यों दोनों के राजस्व में कमी को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के विकल्पों पर गौर किया। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुल कर राजस्व में विभाजनीय राजस्व का हिस्सा संकुचित होता जा रहा है क्यों कि सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार घटक बढ़ रहा है। 15 वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत दिया जाएगा। यह 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के ही स्तर पर है। आयोग के अनुसार, 5 साल की अवधि के लिये सकल कर राजस्व (जीटीआर) 135.2 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। उसमें से, विभाज्य पूल का अनुमान 103 लाख करोड़ रुपए है। विभाज्य पूल में राज्यों का अनुमानित हिस्सा 2021-26 अवधि के लिए 42.2 लाख करोड़ रुपए है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट दो फरवरी को संसद में पेश की गई थी। सिंह ने कहा कि प्रत्येक वित्त आयोग ने विभाजन पूल के प्रतिशत के रूप में राज्यों के हिस्से की कुल राशि में कुछ वृद्धि की है। उन्होंने कहा, ''हमारे पास इस चलन को जारी रखने का एक विकल्प था, हमारे पास इस विचलन को कुछ हद तक बढ़ाने का एक विकल्प था। हमारे पास केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति में संकुचन को देखते हुए इस हिस्से में कुछ कमी करने का भी विकल्प था।

तोमर ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया

नई दिल्ली:

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है और उद्यमियों से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की अपील की है। एक सरकारी बयान के अनुसार कृषि मंत्री शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम और इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा आयोजित %मध्य प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण अवसर% पर एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तोमर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं। उन्होंने उद्यमियों को देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दे रही है। बयान में कहा गया, ÷केंद्रीय मंत्री ने खेती के क्षेत्र में निजी निवेश और नवीनतम तकनीक लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।÷ तोमर ने कहा कि सरकार छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मंत्री ने कहा कि देश में 86 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं। उन्होंने कहा कि गांवों की आत्मनिर्भरता और कृषि क्षेत्र के विकास की कल्पना उनके सशक्तिकरण के बिना नहीं की जा सकती। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार प्रयास है कि छोटे और मझोले किसान भी महंगी फसलों की खेती कर सकें और वैश्विक गुणवत्ता मानकों की फसलों का उत्पादन करने के लिए कृषि-प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त कर सकें।

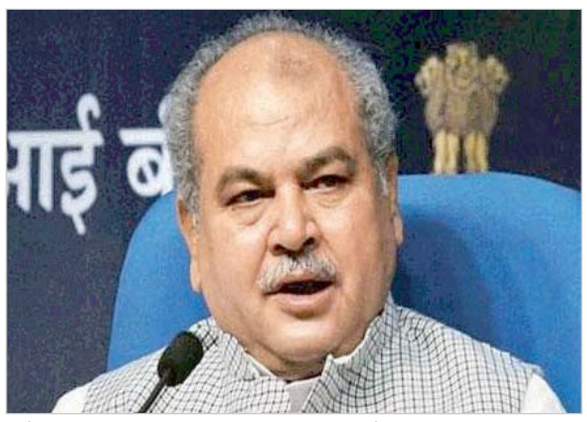

उन्होंने कहा कि आत्मानिभर भारत पैकेज के तहत, कृषि आधारभूत ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो गाँवों में शीत भंडारगृह और गोदामों जैसी बुनियादी सुविधाओं को लाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना कर रही है, जिसका अनुमानित खर्च 6,880 करोड़ रुपए है। एफपीओ में शामिल होने से किसानों को कम लागत, बेहतर बाजार और एकीकृत सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकता है। एफपीओ को ऋण के लिए ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा भंडार में तेज उछाल, जानें 7 दिनों में कितना बढ़ा खजाना

नई दिल्ली: देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 68.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 584.554 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 16.9 करोड़ डॉलर घटकर 583.865 अरब डॉलर रह गया था। इससे पहले इस मुद्राभंडार में पिछले कुछ सप्ताहों से निरंतर तेजी बनी हुई थी। विदेशी मुद्रा भंडार 29 जनवरी 2021 को समाप्त सप्ताह में 590.185 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था।

50.9 करोड़ डॉलर बढ़ा एफसीए

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 26 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां यानी एफसीए के बढ़ने की वजह से मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होती है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में एफसीए 50.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 542.615 अरब डॉलर हो गई। एफसीए को दर्शाया डॉलर में जाता है लेकिन इसमें यूरो, पौंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्रा सम्पत्ति भी शामिल होती हैं।

अब 50 रुपए सस्ता मिलेगा LPG सिलेंडर! इंडियन ऑयल ने बताया तरीका

बिजनेस डेस्क:

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ी हैं। फरवरी के महीने में ही गैस की कीमत तीन बार में 100 रुपए बढ़ी है। वहीं मार्च की शुरुआत में भी गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई यानी फरवरी से अब तक गैस सिलेंडर 125 रुपए महंगा हो चुका है। अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर 819 रुपए का मिल रहा है। ऐसे में आपको गैस सिलेंडर इससे सस्ती कीमत पर तो नहीं मिल सकता है लेकिन एक ऐसा तरीका है, जिससे आपको गैस सिलेंडर 50 रुपए सस्ते में मिल सकता है। इस तरीके के बारे में खुद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया है।

कैसे मिलेगा आपको फायदा

IOC के मुताबिक, अगर आप इंडियन ऑयल का LPG सिलेंडर यानी कि Indane बुक करते हैं, तो इस पर आपको फ्लैट 50 रुपए का फायदा हो सकता है। इसके लिए केवल LPG सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट बुकिंग अमेजन पे से करना होगा। ऐसा करते ही आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा।

बुकिंग और पेमेंट की प्रक्रिया

इसके लिए आपको अमेजन ऐप के पेमेंट ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद अपने गैस सर्विस प्रोवाइडर को चुनें और यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एलपीजी नंबर डालें। आपको अमेजन पे के जरिए पेमेंट करना होगा। अमेजन पे से कैशबैक लेने के लिए 1 मार्च से 1 अप्रैल 2021 के बीच आपको सिलेंडर की बुकिंग करनी होगी। बता दें कि ऑफर सिर्फ पहली बार गैस सिलेंडर की पेमेंट के लिए है। 50 रुपए का कैशबैक तभी मिलेगा जब आप अमेजन पे यूपीआई के जरिए भुगतान करेंगे। भुगतान के तीन दिन में 50 रुपए का कैशबैक आपके अमेजन पे वॉलेट में आ जाएगा।

अब इस नंबर से कराएं सिलेंडर की बुकिंग

इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग-अलग सर्किल के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर होते थे। अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्किल के लिए एक ही नंबर जारी किया है, इसका मतलब है कि अब इंडेन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा।

कोटक महिंद्रा बैंक ने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया

मुंबई: निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को अपने निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। गुलाटी हालिया कृषि कानूनों के प्रबल समर्थक हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय समिति में भी गुलाटी शामिल हैं। बैंक ने शुक्रवार को आधिकारिक बयान में कहा कि गुलाटी का कार्यकाल शनिवार से शुरू होगा। उनका कार्यकाल पांच साल का होगा। कोटक महिंद्रा बैंक के गैर-कार्यकारी चेयरमैन प्रकाश आप्टे ने कहा, ''राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कृषि क्षेत्र पर उनके दृष्टिकोण तथा शोधकर्ता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर लेखक के उनके अनुभव से हमारे बैंक को काफी फायदा होगा।

केन्द्र सरकार को महंगाई पर काबू पाने के लिए समय रहते कदम उठाने चाहिए: गहलोत

जयपुर:

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र सरकार को महंगाई पर काबू पाने के लिए समय रहते कदम उठाने चाहिए वरना लोगों में असंतोष पैदा होगा जो देश हित में नहीं है। गहलोत ने कांग्रेस द्वारा चलाई गई ''स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज मुहिम'' में युवाओं के हिस्सा लेने की प्रशंसा करते हुए कहा, ''कम्पेन (अभियान) आज दिनभर बहुत शानदार चला, लाखों नौजवानों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद देश में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिया है। परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। कम होती आमदनी, जाती हुई नौकरियां और डूबती अर्थव्यवस्था के दौर में लोग जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, ''लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी नीत सरकार को ईंधन की कीमतें कम करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आम आदमी को फायदा देकर उसकी क्रय शक्ति को बढाया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की नौकरियां चली गई है और व्यवसाय बंद हो गए हैं और ऐसी स्थिति में ईंधन की कीमतों में वृद्धि से खाद्य पदार्थों और सब्जियों के दामों में बढोत्तरी होगी और महंगाई बढेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की जिसका सभी ने स्वागत किया, लेकिन बाद में यह पता चला कि पैसा ना तो राज्यों को मिला और नाहीं उद्योगों और व्यासायों को। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडरों पर मिलने वाली राहत भी रोक दी गई है, हालांकि शायद इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। राजस्थान सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वैट में दो प्रतिशत की कमी की जिससे राज्य को 1000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ लेकिन ईंधन की कीमत लगातार बढ रही हैं।

भारत की अपील को OPEC ने किया दरकिनार, सऊदी अरब ने दी स्टॉक में रखे सस्ते तेल के इस्तेमाल की सलाह

नई दिल्ली।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और उसके सहयोगी देशों के जरिए उत्पादन पर लागू नियंत्रण को उठाने की भारत की अपील को अनुसुना कर दिया गया। वहीं इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सऊदी अरब ने भारत से कहा है कि वह पिछले साल जब कच्चे तेल के दाम काफी नीचे चले गए थे, उस समय खरीदे गए कच्चे तेल का इस्तेमाल कर सकता है। कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले ब्रेंट कच्चे तेल का भाव शुक्रवार को करीब एक प्रतिशत बढ़कर 67.44 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। ओपेक और उसके सहयोगी देशों, जिन्हें ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है, ने अपनी बैठक में इस बात पर सहमति जताई है कि अप्रैल में कच्चे तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इन देशों का मानना है कि मांग में और मजबूत सुधार आने देने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

ये की थी अपील

दरअसल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देशों से अपील की थी कि कच्चे तेल के दाम में स्थिरता लाने के लिये वह उत्पादन पर लागू बंदिशों को कम करें। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते कच्चे तेल के दाम से आर्थिक क्षेत्र में आने वाला सुधार और मांग दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। ओपेक देशों की बैठक के बाद भारत के आग्रह के बारे में पूछे गए सवाल पर सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलाजीज बिन सलमान ने कहा कि भारत को पिछले साल काफी कम दाम पर खरीदे गए कच्चे तेल के भंडार में से कुछ तेल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए।

भारत ने किया था भंडारण

भारत ने पिछले साल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम काफी कम दाम पर चल रहे थे, अपने रणनीतिक भंडारों को भरने के लिए एक करोड़ 67 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद की थी।

उस कच्चे तेल का औसत मूल्य 19 डॉलर प्रति बैरल पड़ा था। प्रधान ने 21 सितंबर 2020 को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी थी। बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। तेल कंपनियों ने अगर कच्चे तेल के दाम में आई ताजा वृद्धि को भी ग्राहकों पर डाल दिया तो इनकी खुदरा कीमतें और बढ़ जाएंगी।

GDP में 8% की गिरावट का अनुमान उम्मीद से बेहतर होगा: वित्त मंत्रालय

बिजनेस डेस्क:

चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन जीडीपी (GDP) में 8 फीसदी की गिरावट के अनुमान से बेहतर रहेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह उम्मीद जताई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोनावायरस महामारी के रुख में ठकराव तथा टीकाकरण शुरू होने के बाद अब आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं। मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि विकसित देशों में कोविड-19 की नई लहर और संक्रमण के नए प्रकार के बाद नए सिरे से लॉकडाउन लगाया गया है। इससे वैश्विक उत्पादन में सुधार की रफ्तार कम हुई है लेकिन इसके उलट भारत में कोविड-19 के संक्रमण में गिराट के ग्राफ में हल्के ठहराव के बाद भी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी है और उपभोक्ताओं के आत्मविश्वास में सुधार नहीं डिगा है। टीकाकरण अभियान के बाद उपभोक्ताओं की धारणा सुधरी है।

इसलिए बेहतर होगी अर्थव्यवस्था

रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में महामारी के बाद पहली बार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सकारात्मक हुई है। इससे धारणा बेहतर हुई है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष के अंत तक गतिविधियां जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमान के आकलन की तुलना में बेहतर रहेंगी। इसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक के तीसरी तिमाही के औद्योगिक परिदृश्य सर्वे से भी इस धारणा की पुष्टि होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक रहेगी।

वैक्सीन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक दूरी एक सामाजिक टीके की तरह है। भारत और दुनिया में तेजी से पुनरुद्धार के लिए इस पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए। कोविड-19 टीके के विकास के बाद कई बार इसे नजरअंदाज किया जाता है लेकिन कोविड-19 के टीके के साथ सामाजिक टीका भी जरूरी है। भारत हालांकि महामारी की दूसरी लहर से बचा हुआ है लेकिन आठ राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इससे एक बार फिर सामाजिक दूरी का महत्व सामने आया है।

मोटर वाहनों में अब बढ़ेगी सुरक्षा, सरकार ने यह किया जरूरी

नई दिल्ली:

मोटर वाहनों में जब दुर्घटना होती है तो सबसे ज्यादा खतरा आगे की सीटों पर बैठे लोगों को ही होता है। यदि मोटर वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो तो अगली सीटों पर बैठे लोगों की जान पर बन आती है। इस स्थिति को टालने के लिए सरकार ने अब मोटर वाहनों में अगली सीट पर एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। यह प्रावधान एक अप्रैल 2021 या इससे बाद बने वाहनों पर लागू होगा। अब सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया है, ''वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था।''

कब से होगा लागू

मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद बने वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

हिमाचल कांग्रेस ने राज्य के बजट को दिशाहीन करार दिया, कहा- सरकार बढ़ती महंगाई से नहीं दिला पाई निजात

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किये गए राज्य के बजट को दिशाहीन करार देते हुए कहा कि सरकार लोगों को बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने में नाकाम रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधानसभा में पेश किया गया बजट अधूरा दस्तावेज है, जिसमें राज्य की जनता से झूठे वादे किये गए हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने विधानसभा में जो बजट घाटा पेश किया है, उसमें राज्य के कुल कर्ज और वित्तपोषण के बीच अंतराल का कोई जिक्र नहीं हैं। ठाकुर ने शनिवार को विधानसभा में चौथी बार बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 50,192 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो कोविड-19 संकट के बावजूद पिछले बजट से 1,061 करोड़ रुपये अधिक है। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही कर-रहित बजट पेश करने का दावा कर रहे हों लेकिन इस बात की संभावना भी है कि सरकार वित्तीय घाटे से निपटने के लिये साल के बीच में कर लगा दे। उन्होंने कहा, राज्य की विकास दर नकारात्मक रही है लेकिन मुख्यमंत्री ने पुरानी योजनाओं को नए कलेवर में पेश करके जनता को लुभाने का प्रयास किया है।बजट दिशाहीन और अधूरा दस्तावेज है।

केंद्र सरकार पर बरसे दिग्विजय सिंह, बोले- भाजपा ईवीएम पर निर्भर है

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा कि नए कृषि कानूनों और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर जनता की नाराजगी को लेकर केन्द्र सरकार परेशान नहीं है क्योंकि भगवा पार्टी को चुनाव जीतने के लिये ईवीएम पर भरोसा है। केन्द्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर दिग्विजय अपनी बाजू पर काली पट्टी बांध कर शाजापुर जिले के जयहेड़ा में संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। उन्होंने कहा, '' नवंबर माह में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपये थी, जो अब बढ़कर 890 रुपये हो गयी है। केन्द्र सरकार की उज्जवला योजना के 80 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी इसे खरीदने में असमर्थ हैं।'' मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासन में पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुक्ल 10 गुना तक बढ़ गया है। इससे महंगाई में वृद्धि हुई है और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच नाराजगी देखकर नेता चिंतित हो जाते हैं, लेकिन भाजपा इससे प्रभावित नहीं है क्योंकि वह ईवीएम पर निर्भर है।

गृहमंत्री अमित शाह रविवार को तमिलनाडु और केरल के राजनीतिक दौरे पर जाएंगे

नयी दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तमिलनाडु और केरल के एकदिवसीय राजनीतिक दौरे पर जाएंगे, जहां वह घर-घर प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि शाह तिरूवनंतपुरम में भाजपा की ''केरल विजय यात्रा'' के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह दोनों राज्यों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कन्याकुमारी के सुचिंद्रम में ''वेटरी कोडी एनाधी'' (चुनावी जीत के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम) की शुरुआत करने के अलावा शाह वहां एक रोडशो भी करेंगे, जहां कांग्रेस के निवर्तमान सांसद की मौत के कारण खाली हुई सीट पर भाजपा लोकसभा उपचुनाव भी लड़ रही है। भाजपा सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के साथ मिलकर राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रही है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में छह अप्रैल को एक चरण में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई असम के शिवसागर से लड़ेंगे चुनाव

गुवाहाटी। जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई असम विधानसभा चुनाव में अपनी नवगठित पार्टी राइजर दल के उम्मीदवार के तौर पर शिवसागर सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए राइजर दल के कार्यकारी अध्यक्ष भास्को डी सैकिया ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष गोगोई शिवसागर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण में राइजर दल 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि, एक सीट पर उसकी ओर से अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना बाकी है। वहीं, दूसरे चरण में छह सीटों पर किस्मत आजमाएगी।

अब महाराष्ट्र से एमपी आने वाले लोगों के लिए जरूरी होगा कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिये कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये आधिकारिक बयान में बताया गया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिये हैं। समीक्षा बैठक में चौहान ने कहा, '' भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैन और महाराष्ट्र से लगे जिलों में कोरोना से प्रभावित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है।

अदालतों में मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता : राष्ट्रपति कोविंद

जबलपुर। (एजेंसी)।

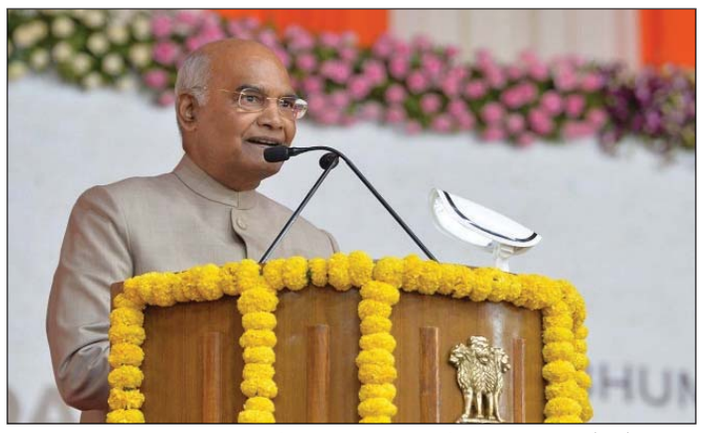

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए जिला अदालतों के न्यायाधीशों के साथ-साथ अर्द्ध-न्यायिक कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत पर शनिवार को जोर दिया। राष्ट्रपति ने यहां अखिल भारतीय राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, ''अब जरूरत है कि देश की अदालतों, विशेष रूप से जिला अदालतों में लंबित मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण करने के लिए न्यायाधीशों के साथ-साथ अन्य न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया जाए।''

उन्होंने कहा, ''इनके बीच, ज्ञान एवं सूचना के आदान-प्रदान के लिए ऐसे सम्मेलनों के अलावा, कोई अन्य स्थायी मंच स्थापित किया जा सकता है। इससे, एक ओर जहां मुकदमों के निस्तारण में तेजी आ सकती है, वहीं न्यायिक प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में अखिल भारतीय परिदृश्य का भी विकास हो सकता है।'' सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी (एमपीएसजेए) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। कोविंद ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए एमपीएसजेए के प्रयासों की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने न्यायिक प्रणाली में तकनीक के उपयोग में वृद्धि का भी स्वागत करते हुए कहा कि देश में 18,000 अदालतों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालतों में की गई।'' कोविंद ने कहा, ''अब ई-अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ई-कार्यवाही, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केन्द्रों की सहायता से जहां न्याय-प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज के इस्तेमाल में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव हुआ है।''

उन्होंने कहा, '' कुछ उच्च न्यायालय भी स्थानीय में अदालती फैसलों का अनुवाद कराने लगे हैं। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन अब मेरी अपेक्षाएं कुछ और बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूं कि सभी उच्च न्यायालय, अपने-अपने प्रदेश की अधिकृत में, जन-जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद, उच्चतम न्यायलय की तरह एक ही समय पर उपलब्ध व प्रकाशित कराएं। राष्ट्रपति ने उनके सुझाव पर शीर्ष अदालत द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद नौ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की प्रशंसा की। राष्ट्रपति शनिवार से मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

योगी आदित्यनाथ ने रामायण की विभिन्न घटनाओं का किया जिक्र, बोले- इसमें विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए शनिवार को कहा कि इस महाकाव्य में विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय है। मुख्यमंत्री शनिवार को यहां संत गाडगे सभागार में रामायण विश्व महाकोश (ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण) की 'कर्टेन रेजर' पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किया था। उन्होंने कहा,'' यह पुस्तक हमें विज्ञान और आध्यात्म के अनछुए पहलुओं से परिचित कराएगा।'' कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 'रामायण विश्व महाकोश' को ई-बुक के रूप में भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान रामायण विश्व महाकोश पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम की संस्कृति पहली संस्कृति है, जिसने वैश्विक मंच पर अपना स्थान बनाया। इसके हजारों वर्ष बाद भगवान बुद्ध की संस्कृति वैश्विक मंच पर स्थापित हुई।

किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे, प्रदर्शनकारी किसानों ने एक्सप्रेस-वे पर आवागमन रोका

चंडीगढ़। (एजेंसी)।

केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली की सीमा पर अपने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को हरियाणा में छह लेन वाले कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर कुछ स्थानों पर यातायात अवरुद्ध कर दिया। किसानों का प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो अपराह्न चार बजे तक जारी रहा। काले झंडे थामे तथा बांह पर काली पट्टी बांधे किसानों और काला दुपट्टा पहने महिला प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे नहीं माने जाने को लेकर भाजपा नीत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोनीपत तथा झज्जर और कुछ अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली तथा अन्य वाहन लेकर आए और उन्हें केएमपी एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में बीच में खड़ा कर दिया।

हरियाणा पुलिस ने यातायात का मार्ग बदलने के लिये प्रबंध कर रखा था। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक्सप्रेस-वे पर यातायात अवरूद्ध करने का आह्वान किया था। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे 136 किलोमीटर लंबा है। मानेसर-पलवल खंड 53 किलोमीटर लंबा है और इसका उद्घाटन 2016 में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, वहीं 83 किलोमीटर लंबे कुंडली-मानेसर खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में किया था। भारतीय किसान यूनियन (दाकुंडा) के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा, '' हम केएमपी एक्सप्रेस-वे पर यातायात अवरुद्ध करेंगे लेकिन आपात सेवा में लगे वाहनों को जाने दिया जाएगा।''

सोनीपत में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, '' तीनों कृषि कानूनों को वापस लिये जाने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे।'' किसानों ने पलवल जिले में भी प्रदर्शन किया। केएमपी एक्सप्रेस-वे दिल्ली की हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़कों पर भीड़ को कम करने खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में आने वालों ट्रकों की संख्या को कम करने के लिए बनाया गया था। इससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिली। गौरतलब है कि हजारों की संख्या में किसान केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले वर्ष नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों की आशंका है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और उन्हें बड़े कॉर्पोरेट घरानों के 'रहमोकरम' पर छोड़ देंगे। हालांकि, सरकार का कहना है कि नए कानून किसानों के लिए बेहतर अवसर लाएंगे और इससे कृषि के क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी भी आएगी।

बंगाल चुनाव : भाजपा ने 57 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे चुनाव

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 57 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसके अनुसार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अशोक डिंडा और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष भी भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने वालों में शामिल हैं।

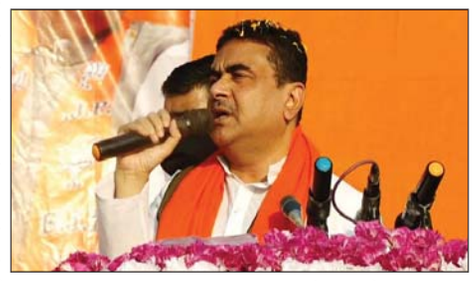

उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक सीट अपने सहयोगी दल एजेएसयू को दी है। इसके साथ ही पार्टी ने 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में होने वाले चुनाव के पहले दो चरणों के लिए 60 में से तीन को छोड़कर बाकी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सिंह ने कहा कि राज्य में ÷जंगल राज÷ की स्थिति है और मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस को हराकर भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद उनकी यह पहली रैली होगी। नंदीग्राम में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन ने 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया था। नंदीग्राम में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी और अब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अधिकारी 2016 में इस सीट से विजयी हुए थे और हाल में भगवा पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली का भी अपना शिक्षा बोर्ड होगा

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब अलग से दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये बोर्ड तीन लक्ष्य पूरे करेगा। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो आने वाले समय में हर क्षेत्र में देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हों। हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनें और ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस को हम स्कूलों और बोर्ड में लेकर आएंगे। इस साल 20-25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि 4-5 साल में स्वेच्छा से सारे सरकारी, निजी स्कूल बोर्ड में शामिल हो जाएंगे।

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली में आखिर अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि छह साल पहले हमने बजट का 25 फीसदी पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करना चालू किया। इससे सरकारी स्कूलों की इमारत अच्छी बनने लगी, लैब्स बनने लगे, साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था हुई इत्यादि। उन्होंने कहा कि हीन भावना से ग्रसित सरकारी स्कूलों का ढांचा बदला गया। हमने दूसरा परिवर्तन किया कि शिक्षकों और प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग के लिए अच्छी जगह भेजा। उन्हें क्रैम्बिज में प्रिशिक्षण दिया गया।

बेगूसराय में गरजे गिरिराज, बोले- अगर अधिकारी नहीं सुनता है तो बांस उठाकर मारो !

पटना। (एजेंसी)।

भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बार गिरिराज सिंह ने अधिकारियों जमकर क्लास लगाई। बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है तो उसकी बांस उठाकर पिटाई करिए।

भाजपा नेता ने जनता से कहा कि आप मालिक हैं लोकतंत्र में, सांसद, एमएलए, पीएम, एसडीओ, ज्यूडिशरी ये आपके अधीन है। आप अपनी अच्छी बात लेकर के जाएं। एक मित्र ने लिखकर दिया कि सीओ गड़बड़ी कर रहा है। आप जाइये, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यह आपका अधिकार है और अगर आपके अधिकार का हनन होता है तो गिरिराज आपके साथ खड़ा हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि आपने मुझे सांसद बनाया है। आपने किसी को जिलापरिषद बनाया है। आपके बल पर कोई मुखिया बनाया है। मुखिया, एमएलए, एमपी के बल पर आप नहीं हैं। यह ध्यान में रखिए और मनोबल को ऊंचा रखिए। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कोई सुनता नहीं है तो दोनों हाथ से बांस से मारो न। ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनता है।

अमित शाह और राजनाथ सिंह हैं किसान लेकिन कृषि मंत्री तोमर नहीं ! 538 में 216 सांसदों का दस्तावेजों में जिक्र

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संसद के करीब पार्क में खेती करने की बात कही है। जबकि सरकार का कहना है कि नए कानून कृषि सुधारों की दिशा में अभूतपूर्व कदम है। इससे किसानों को लाभ होगा। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। जो यह दर्शाती है कि देशवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने सांसद किसान है।

हिन्दी न्यूज वेबसाइट %दैनिक भास्कर% की एक रिपोर्ट के मुताबिक 538 सांसदों में से 216 सांसद किसान हैं। दरअसल, बजट सत्र 2021-22 के दौरान संसद में कृषि कानूनों के विषय पर जमकर हो-हल्ला हुआ। अधिकतर विपक्षी सांसद इसके विरोध में तो कुछ ही इसके समर्थन में दिखाई दिए। यहां तक की पहले कृषि कानूनों को समर्थन करने वाले कुछ सांसदों ने विरोध प्रदर्शन को बड़ा होता देख, अपना नजरिया बदला और इसका विरोध करने लगे। इस बार के सत्र में तो कई नेताओं ने यहां तक कहा कि वह भी किसान हैं और वह इनका दर्द जानते हैं। इसी आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें दावा किया गया कि संसद की 5 खाली सीटों को छोड़ दिया जाए तो 538 में से 216 सांसदों ने सरकारी दस्तावेजों में खुद को किसान बताया है।

किस पार्टी के पास कितने किसान ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के पास 302 सांसदों में से 139 किसान सांसद हैं। जबकि कांग्रेस के पास 51 में से 13, द्रमुक के पास 24 में से 10, तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 1, वाईएसआर कांग्रेस के 21 में से 6, शिवसेना के पास 18 में से 11, जदयू के 16 में से 7, बीजद के 12 में से 2, बसपा के 10 में से 5, टीआरएस के 9 में से 5, लोजपा के 6 में से 4 इत्यादि किसान सांसद हैं।

रिपोर्ट्स में किसानों और किसान सांसदों के महीनेभर की आय का भी उल्लेख किया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नाबार्ड (ह्क्क्रष्ठ) के आंकड़ों के मुताबिक हिन्दुस्तान का किसान महीने में औसतन 8,931 रुपए कमाता है। जबकि सांसदों को सभी सुविधाओं के बावजूद हर माह 2 लाख 30 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। अगर हम कोरोना महामारी की वजह से सांसदों की घटी तनख्वाह की बात करें तो अभी उन्हें 1 लाख 73 हजार रुपए मिलता है। हालांकि, सबकुछ सही रहा तो कुछ वक्त बाद सांसदों को वापस से पुरानी तनख्वाह मिलने लगेगी।

मोदी कैबिनेट में कितने किसान सांसद ?

इस रिपोर्ट की सबसे चौंका देने वाली बात तो यह रही कि मोदी सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान सांसद नहीं हैं। जबकि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई किसान सांसद हैं। मोदी सरकार में कुल 21 केंद्रीय मंत्री और 32 राज्यमंत्री हैं। ऐसे में 21 केंद्रीय मंत्रियों में 7 और 32 राज्यमंत्रियों में 13 किसान हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं वाणी कपूर

अभिनेत्री वाणी कपूर ने कहा है कि वह भविष्य में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। वाणी ने कहा, ''बॉलीवुड में आने से पहले से ही समग्र जीवन शैली मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रही है। मेरे लिए हमेशा से स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, बाहर काम करना और सही भोजन करना पहली प्राथमिकता रही है। मैं इस क्षेत्र में कुछ बनाना चाहती हूं, काम करना चाहती हूं। आने वाले सालों में इस क्षेत्र में भी कदम रखूंगी और इसके लिए मैं कई साल से रिसर्च भी कर रही हूं।'' वाणी ने आगे कहा, ''मैं अपने देश के नागरिकों के बीच स्वास्थ्य की महत्ता के बारे में जागरुकता लाना चाहती हूं क्योंकि हमेशा स्वस्थ रहना हम सभी के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वैसे भी यह काम करना बहुत मुश्किल नहीं है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। मेरे पास इस क्षेत्र में काम करने को लेकर कई रोमांचक विचार हैं, लेकिन अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। साथ ही मुझे लोगों के लिए एक उदाहरण भी पेश करना होगा, ताकि वो मेरे विजन पर भरोसा करें।'' काम को लेकर बात करें तो वाणी कपूर की अगले कुछ महीनों में 3 बैक-टू-बैक फिल्में- बेलबॉटम, शमशेरा और चंडीगढ़ करे आशिकी रिलीज होने वाली हैं।

राहुल वैद्य ने बताया दिशा परमार संग कब लेंगे सात फेरे

'बिग बॉस 14' के रनरअप और सिंगर राहुल वैद्य काफी समय से अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बिग बॉस के घर में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार को शादी के लिए प्रपोज किया था। अब उन्होंने कहा है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार से अगले तीन-चार महीने के अंदर शादी रचा लेंगे। राहुल वैद्य ने एक इंटरव्यू में कहा, हम अभी शादी की तारीख तय करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हालांकि, हमारी शादी तीन-चार महीनों के अंदर हो जाएगी। हम दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के हैं। हम किसी भी चीज को लेकर बहुत जिद्दी नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैंने कई शादियों में परफॉर्म किया है और सब कुछ शानदार होता देखा है। उनकी शादी साधारण तरीके से होगी और इसमें काफी कम लोग शामिल होंगे। राहुल ने बताया कि वे अपनी शादी के बाद एक फंक्शन रखेंगे, जिसमें सभी दोस्त, परिवार, करीबी लोग शामिल होंगे। वहीं दिशा ने राहुल के प्रपोजल के बारे में बताया, मैं दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी, तभी टीवी पर उनका मुझे प्रपोज करते हुए प्रोमो दिखाया गया। मैं हैरान थी, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेंगे। हम डेट तो कर ही नहीं रहे थे कि सीधा प्रपोजल पर आ जाए। दिशा ने बताया कि वह राहुल को पसंद करती थीं, लेकिन प्रपोजल के बाद वह आश्चर्यचकित थीं। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया था। इन दोनों के प्रपोजल को देखकर उनके परिवार को भी सरप्राइज मिला। शो में प्रपोजल का प्रोमो देखकर दिशा भावुक होकर रोने लगी थीं। दिशा ने कहा, इस दरमियान चीजों को समझने में वक्त लगा और प्रपोजल को ना कहने का सवाल ही नहीं था। दिशा ने बताया कि उनके और राहुल के बीच 2018 में इंस्टाग्राम पर चैटिंग शुरू हुई थी। दिशा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी कि उन्हें राहुल का गाना बहुत पसंद आया। इसके जवाब में राहुल ने प्रतिक्रिया दी थी 'लव इट'। बता दें कि दिशा परमार सीरियल 'प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यार' में नजर आई थीं। 'बिग बॉस 14' के घर से बाहर आने के बाद राहुल अपनी गर्लफ्रेंड दिशा से मिले और तब से उनके साथ विदेश में छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। समय-समय पर यह कपल तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है।

निगेटिव किरदार निभाना 'एक सीखने का अनुभव'

अभिनेता तनुज विरवानी आगामी सीरीज 'कामठीपुरा' में निगेटिव भूमिका में नजर आएंगे। उनका कहना है कि श्रृंखला में उनकी भूमिका एक सीखने का अनुभव है और भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक अच्छा उछाल बोर्ड है। अभिनेता 'कमाठीपुरा' में एक डॉन की भूमिका में हैं, वहीं 'तंदूर' और 'कार्टेल' शो में निगेटिव शेड्स में दिखाई देंगे। तनुज ने बताया, ''इसमें कई परतों और बारीकियों के साथ एक जटिल भूमिका निभाने का एक अनुभव है। इसने 'तंदूर' और 'कार्टेल' के लिए एक अच्छा उछाल वाला बोर्ड दिया, जहां मैं निगेटिव किरदार भी निभाता हूं।'' कमाठीपुरा में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा, ''मैं कामठीपुरा के स्थानीय शासक डॉन प्रहार का किरदार निभा रहा हूं। ड्रग्स, हवाला और वेश्यावृत्ति में वह लिप्त है। उसके पास पुलिस के मुखबिर भी हैं।

जरीन खान बनीं डॉक्टर

हाल ही में, गोवा में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवॉर्ड्स 2020 का आयोजन किया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नजर आईं। अवॉर्ड शो में उपस्थित जरीन खान न केवल गेस्ट ऑफ ऑनर थीं, बल्कि उन्हें अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल पीस द्वारा माननीय डॉक्टरेट के रूप में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया, जिससे अब वे डॉ.जरीन खान बन गई हैं। गोवा के सीएम, प्रमोद सावंत ने जरीन को सम्मान प्राप्त करने के लिए बधाई दी। उनके अलावा भारतीय सेना के गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे, जिनमें प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी डायरेक्टर वीए, लिएंडर पेस और संग्राम सिंह भी उपस्थित थे। बता दें कि जरीन खान सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं और फैंस उनके हर स्टाइल को फॉलो करते हैं। जरीन खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 आई सलमान खान की फिल्म 'वीर' से की थी। बॉलीवुड के अलावा एक्ट्रेस ने तेलुगू और पंजाबी सिनेमा में भी हाथ आजमाया है।

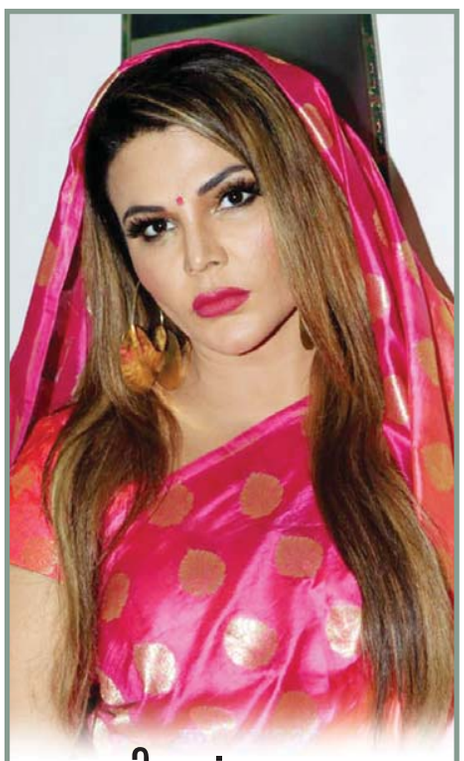

राखी सावंत का खुलासा जावेद अख्तर बनाना चाहते हैं उनकी बायोपिक

ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने 'बिग बॉस 14' के घर में दर्शकों का खूब एंटरटेन किया। इस शो में बतौर चैलेंजर हिस्सा लेने के बाद राखी शो की टॉप फाइनलिस्ट में से एक बनकर उभरीं। इस बीच राखी सावंत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले काफी समय से चर्चा है कि राखी सावंत के जीवन पर फिल्म बनने वाली है। हाल ही में जब राखी सावंत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। राखी ने कहा, मेरे पास मशहूर गीतकार जावेद अख्तर जी का फोन आया था। हम फ्लाइट में बैठे थे। वह मेरे जीवन पर फिल्म बनाना चाहते हैं। राखी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बायोपिक पर कहा, यह करीब एक साल पुरानी बात है। मेरे पास जावेद अख्तर जी का फोन आया था। जावेद जी ने कहा कि मैं तुम्हारी बायोपिक लिखना चाहता हूं तो मुझसे मिलो, लेकिन उस दिन के बाद मैं उनसे मिली ही नहीं। वह चाहते हैं कि मुझ पर बायोपिक बने। उन्होंने आगे कहा, मेरी बायोपिक बहुत विवादित होगी। पता नहीं देश की जनता देखना चाहेगी या नहीं। जब राखी से पूछा गया कि वह अपनी भूमिका में किसे देखना चाहेंगी। इस पर उन्होंने कहा, मैं तो चाहती हूं कि आलिया भट्ट मेरा किरदार निभाएं, पर मुझे नहीं पता कि जावेद जी मुझे ही फिल्म में साइन करेंगे, आलिया को लेंगे या प्रियंका चोपड़ा को। राखी ने कहा, मेरी चाहत तो मैं खुद हूं, लेकिन अगर मैं ना करूं तो आलिया करें। दीपिका, आलिया, करीना जो भी कर पाएं। ये सब नंबर वन हैं और सभी मेरी पसंद हैं। इन दिनों राखी की मां का कैंसर का इलाज चल रहा है। इस पर उन्होंने कहा, मां की तबीयत अभी ठीक है। उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। यह नहीं कहूंगी कि वह बहुत अच्छी हैं पर हां कीमो के बाद वह पहले से ठीक महसूस कर रही हैं। उनकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है। अभी कीमोथेरेपी की तीन सिटिंग और हैं।

फरहान अख्तर की फिल्म में दिखेंगी आलिया भट्ट

एक्ट्रेस आलिया भट्ट के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों की मानें तो आलिया को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा -2 में देखने को मिलेगा। इस फिल्म का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। इस फिल्म में आलिया के अलावा दो और फीमेल लीड एक्ट्रेस को शामिल करने की बात चल रही है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि फिल्म को अगले साल शुरू किया जाएगा।

बालाजी मीडिया के खिलाफ सुनील शेट्टी ने दर्ज करवाई शिकायत

बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने फर्जी फिल्म पोस्टर साझा करने के लिए मुंबई के एक प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि शेट्टी फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शेट्टी ने वर्सोवा थाने में बुधवार को यह शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि शेट्टी ने बालाजी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पर उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया कि वह फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। अधिकारी के अनुसार 59 वर्षीय अभिनेता ने आरोप लगाया कि निर्माता ने फिल्म का फर्जी पोस्टर साझा किया, जिससे वह जुड़े नहीं हैं। यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्टर के दिखने के बाद सामने आई। शिकायत का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि शेट्टी ने आरोप लगाया है कि कंपनी लोगों से संपर्क कर रही है और उनके नाम पर रुपये मांग रही है। इस पूरे मामले में वर्सोवा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सिराज इनामदार ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है, लेकिन अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। किसी को भी बयान दर्ज कराने के लिये नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है।

सोनाक्षी सिन्हा ने की अगली फिल्म 'बुलबुल तरंग' की घोषणा

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपन अगली परियोजना की घोषणा की। अभिनेत्री को अगली बार ओटीट रिलीज बुलबुल तरंग में देखा जाएगा। अभिनेत्री ने खुद की एक तस्वी पोस्ट की जिसमें वह नीली सलवार कमीज में काफी सुंदर दिखाई दे रह हैं। शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, ''बुलबुल से मिलं एक लड़की अपने सपने को सच करने के लिए बाहर निकली। मेरी अगल फिल्म बुलबुल जल्द ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग को तैयार।'' फिल्म क श्रीनारायण सिंह ने निर्देशित किया है और कहा जाता है कि यह एक सच्च कहानी से प्रेरित है। फिल्म में राज बब्बर और ताहिर राज भसीन भी हैं सोनाक्षी सिन्हा दबंग, लुटेरा, अकीरा और मिशन मंगल में अपनी भूमिक के लिए जानी जाती हैं, वह अपनी अगली फिल्म भुज : द प्राइड ऑफ इंडिया पर काम कर रही हैं। सोनाक्षी के अलावा, फिल्म में अजय देवगन संजय दत्त, शरद केलकर, अम्मी विर्क, प्रणिता सुभाष और नोरा फतेह भी होंगी

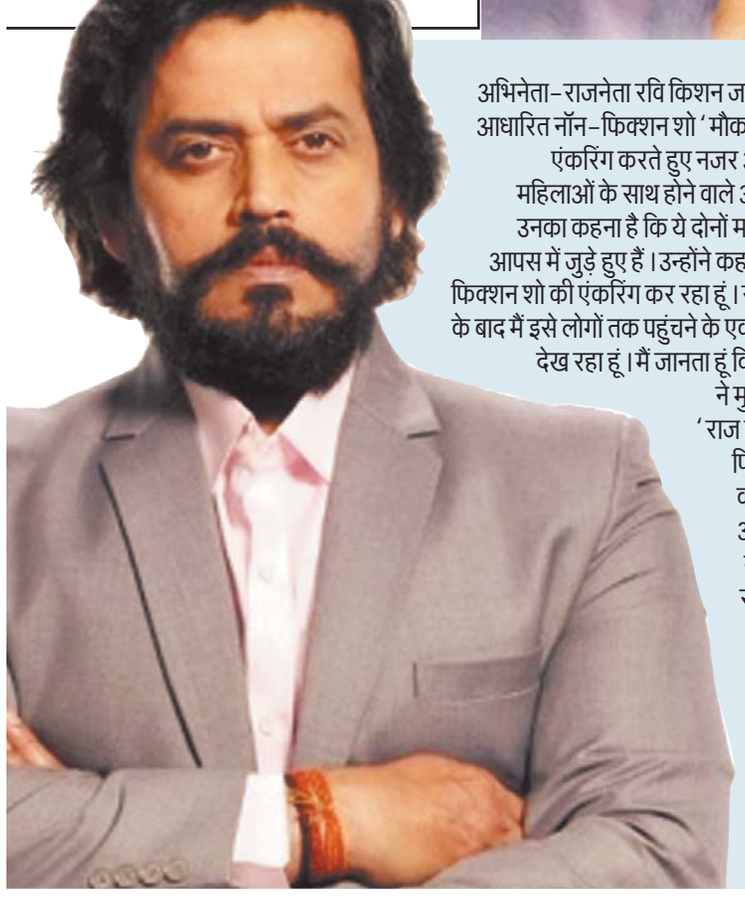

ड्रग्स और यौन शोषण के मामले आपस में जुड़े हुए हैं

अभिनेता-राजनेता रवि किशन जल्द ही अपराध पर आधारित नॉन-फिक्शन शो 'मौका-ए-वारदात' में एंकरिंग करते हुए नजर आएंगे। ड्रग्स और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर उनका कहना है कि ये दोनों मामले कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, ''मैं एक नॉन-फिक्शन शो की एंकरिंग कर रहा हूं। राजनीति से जुड़ने के बाद मैं इसे लोगों तक पहुंचने के एक मौके के तौर पर देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि किस तरह टीवी ने मुझे 'बिग बॉस 1', 'राज पिछले जनम का' और 'झलक दिखला जा 5' के जरिए फिर से स्थापित होने का मौका दिया। लेकिन 'मौका-ए-वारदात' शो करने के पीछे मेरा एक मकसद है।'' उन्होंने आगे कहा, ''मुझे इस शो का विचार अच्छा लगा। यह शो देश के हर राज्य और दूरदराज के गांवों से कहानियां ला रहा है, जहां अपराध होते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस शो के पीछे का आइडिया यह है कि लोग स्थानीय स्तर पर होने वाली चीजों के बारे में जागरूक हों। इसके अलावा प्रोडक्शन टीमों के उन गांवों में जाने से स्थानीय लोगों को भी काम मिलता है। यह यूपी में फिल्म सिटी बनाने के विचार से भी जुड़ा है। मैं गोरखपुर का सांसद भी हूं तो मेरी बात को लोग गंभीरता से भी लेंगे। मैं लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता हूं। इसीलिए मैंने यह शो करने का फैसला किया है।'' शो का हर एपिसोड एक असल कहानी बताएगा और अपराध के पीछे की सच्चाई का खुलासा करेगा। इस शो में लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और कलाकार सपना चौधरी भी हैं। रवि किशन ने शो को लेकर कहा, ''मैं दृढ़ता से मानता हूं कि ड्रग्स और यौन शोषण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें नशीली दवाओं के सेवन के खिलाफ लड़ना होगा, यह युवाओं को महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध करने की ओर ले जाता है। हमारे पास आबादी के मुताबिक पुलिस नहीं है। हमें लोगों को जागरूक करके भी अपराधों को रोकना होगा। इस शो के जरिए हम यही कर रहे हैं। वैसे भी ये दोनों मुद्दे समाज के लिए अहम हैं, यह न केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि यह युवाओं को बर्बाद भी कर रहा है।'' धारावाहिक 'मौका-ए-वारदात' 9 मार्च से एंड टीवी पर शुरू होने जा रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कोंडापल्ली खिलौने

लकड़ी से बने खिलौने अब बच्चों की दुनिया से गायब हो रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय से हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। ये देखने में तो आकर्षक होते ही हैं, साथ ही तुम्हें ग्रामीण जीवन से भी रूबरू कराते हैं। आज इनके बारे में जानते हैं

कहां है तुम्हारा खिलौनों का संसार..कितने खिलौने हैं तुम्हारे पास.. वीडियो गेम, रिमोट वाली कार, बार्बी डॉल, रोबोट यही सब ना। जब भी मम्मी के साथ बाजार जाते हो, एक नया खिलौना तो लाते ही हो। लेकिन कोई लकड़ी से बना हुआ खिलौना है क्या तुम्हारे इस चहेते भंडार में- खोजो जरा उसे।

क्या तुम्हें पता है कि नई चीजों को समझने व सीखने के लिए पढ़ना ही सबसे जरूरी काम नहीं, खेल के द्वारा भी तुम कई नई चीजों के बारे में जान सकते हो। कई ऐसी सीख हैं, जो हमें बस खेल से मिल जाती हैं और खिलौना तो हम किसी भी वस्तु को बना सकते हैं। अब शेर के बच्चे को ले लो, वो तो अपनी मां की पूंछ को खिलौना बनाकर खेलते हैं। यहां तक कि हमारे खुद के खिलौनों में कई बार रसोई के बर्तन, जैसे चम्मच या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स शामिल होते हैं।

कोंडापल्ली खिलौने

कोई लकड़ी का टुकड़ा देकर उसका उपयोग करने को कहे तो तुम क्या कर सकते हो? या तो पेपर वेट बनाओगे या अपने दरवाजे को हवा से बंद न हो तो ब्रेकर की तरह उपयोग करोगे बस। लेकिन कोंडापल्ली कारीगर को वही टुकड़ा दो, देखो वे अपने हाथ के जादू से किस तरह उसमें रंग भर तुम्हारे लिए खूबसूरत खिलौना बना देंगे।

भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली, निर्मल, एट्टीकोपक्का और तिरुपति लकड़ी के खिलौने के लिए जाने जाते हैं।

आंध्र प्रदेश स्थित विजयवाड़ा जिले में बने लकड़ी के कोंडापल्ली खिलौने काफी प्रसिद्ध है। जो कारीगर इस पेशे में हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की आजीविका इसी कला पर निर्भर है। कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश का एक औद्योगिक कस्बा है, जिसकी पहचान ही इन खिलौने के कारण है।

कैसे बनते हैं ये

इन खिलौनों को बनाना बच्चों का खेल नहीं। इनकी डिजायनिंग में काफी लंबा समय लगता है। इस क्षेत्र के दस्तकार हल्की लकड़ी जिसे पुंकी लकड़ी के नाम से जाना जाता है, से इन खिलौनों को बनाते हैं। यह काफी मुलायम होती है और आसानी से मुड़ा भी जाती है। सबसे पहले लकड़ी को इतना गर्म किया जाता है कि इसमें नमी न रहे। फिर जो खिलौने की आकृति बनाई जानी है उसके अलग-अलग हिस्से बनाए जाते है। इन हिस्सों को जोड़ दिया जाता है, फिर इन पर प्राकृतिक और एनामिल रंग लगाए जाते है, फिर पतले हल्के ब्रश से इन पर पेंटिंग बनाई जाती है। इन चित्रकारियों में पशु-पक्षी, ग्राम्य जीवन, देवी-देवताओं तथा सैनिकों आदि की आकृतियां बनाई जाती हैं। ये खिलौने देखने मे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।

खिलौनों की थीम

इन खिलौनों को जानवरों और ग्रामीण जीवन को देखते हुए डिजायन किया जाता है। हंस, मोर और तोता इसके लिए लोकप्रिय थीम हैं। कुछ जिंदगी के प्रसंग को भी खिलौने बनाने में थीम की तरह उपयोग किया जाता है। जैसे कुएं से पानी खींचती महिला, सपेरे, हाथी के साथ महावत आदि। इसके साथ ही भगवान को भी आकार दिया जाता है, जैसे कृष्ण- इन्हें बांसुरी बजाते और गायों से घिरा हुआ दिखाते हैं।

बहुत-कुछ सिखाते हैं

ये खूबसूरत कोंडापल्ली खिलौने जिंदगी में सीख तो देते ही हैं, साथ ही रंग और खुशी भी भरते हैं। ये ग्रामीण जिंदगी से रूबरू कराते हैं। आज बार्बी डॉल ने भले ही पुराने खिलौनों की जगह ले ली है, लेकिन इन पुराने कोंडापल्ली खिलौनों की यादें सबके दिल में बसी रहेंगी।

कितने पुराने खिलौने

भारत में 5,000 वर्ष पुराने हड़प्पा संस्कृति के खिलौने अब तक मौजूद हैं। ये खिलौने प्राकृतिक चीजों से जैसे क्ले, लकड़ी और पत्थरों से बने हैं। और तो और ये प्राचीन खिलौने बाद में हाथों से बनाए गए खिलौनों से काफी मेल खाते हैं।

कुछ ऐसी है सांपों की दुनिया...

दुनियाभर में करीब 2500 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। इनमें अपने देश में ही लगभग 250 तरह के सांप हैं। सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में करीब 50 प्रजाति के जहरीले होते हैं। इनमें कोबरा, मनीर, गोनस व फर्सा सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। सबसे जहरीला सांप ऑस्ट्रेलियन टाइगर है और विषैले सांपों में सबसे लंबा सांप किंग कोबरा है। किंग कोबरा नाग नहीं होता, लेकिन नाग की तरह फन निकालता है। वैसे विश्व का सबसे लम्बा सांप एनाकोंडा है, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन यह जहरीला नहीं होता है। भारत में सबसे लंबा सांप रेटिक्युलेटेड पायथन है और यह भी जहरीला नहीं होता है। भारत का सबसे जहरीला सांप मनीर है। इसमें नाग की अपेक्षा दस गुना अधिक जहर होता है। मनीर का शरीर काला-नीला होता है, उस पर सफेद धारियां होती हैं। यह दिन में आराम करता है और रात में शिकार।

हवा से चलती है यह कार

इंटरनेट पर दोस्त बने रोमानिया के राउल ओएदा और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव समारटिनो ने बातों-बातों में इस तकनीक पर चर्चा की और इसको बनाने की ठानी। लेगो ब्लॉक से बनी और हवा से चलनेवाली इस कार की अधिकतम रफ्तार 30 किमी प्रति घंटा है। रोमानियाई तकनीशियन और ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी ने इस कार को बनाने के लिए 5,00,000 लेगो ब्लॉक का इस्तेमाल किया। बेहद खर्चीले इस प्रोजेक्ट के लिए स्टीव समारटिनो ने आधी रात में ट्विट किया ''कोई है जो 500 से 1000 डॉलर लागत के एक प्रोजेक्ट में निवेश कर सकता है, जो बेहद अद्भुत और दुनिया का पहला प्रोजेक्ट होगा, कम से कम 20 सहयोगी चाहिए।'' और देखते ही देखते 40 ऑस्ट्रेलियाई नकद देने के लिए आगे आए और इस तरह 'ऑसम माइक्रो प्रोजेक्ट' का जन्म हुआ। पता है दोस्तों, इस कार को बनाने में 18 महीने का वक्त लगा और लगभग 60 हजार अमेरिकी डॉलर के खर्च हुए, जो सामूहिक योगदान से इकट्ठा किया गया। इस कार की खासियत यह है कि पहिया छोड़कर सब कुछ लेगो ब्लॉक का बना हुआ है। हवा से चलनेवाले चार इंजन और 256 पिस्टन कार को शक्ति प्रदान करते हैं।

हाथी भी जताते हैं दु:ख उनमें भी हैं भावनाएं

एक समय तक हमारी धारणा यही थी कि संसार में भावनाएं सिर्फ मनुष्यों में ही पाई जाती हैं किन्तु बाद में पता चला कि इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं और फिर जैसे-जैसे विज्ञान ने विकास किया पेड़-पौधों पर अध्ययन हुए तो पेड़-पौधों में भी भावनाओं का पाया जाना स्पष्ट हो गया। अब यह तय है कि भावनाएं अथवा संवेदनशीलता सभी प्राणियों में पाई जाती है।

दोस्तों, आपने भी कई बार अपने आसपास उपस्थित जानवरों में भावनाओं को महसूस किया होगा... कभी अपने पालतू को अपनों से बिछड़ने पर रोते देखा होगा या कई बार उसे किसी अन्य तरीके से सामान्य से हटकर कुछ अलग तरह का व्यवहार करते देखा होगा। जानवरों में कौन कितना अधिक भावुक है इसकी व्याख्या हाल ही में अमेरिका के विलियम एंड मेरी कॉलेज के मानव विज्ञान की प्रोफेसर बारबरा जे किंग ने अपनी एक पुस्तक 'हाउ एनीमल्स ग्रीव' में की है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने जानवरों की कई प्रजातियों पर अध्ययन को लोगों के साथ शेयर किया है। उनकी व्याख्या बताती है कि दु:ख व्यक्त करने में हाथी सबसे अधिक भावुक जानवर है। किताब में उन्होंने जानवरों की कई प्रजातियों के द्वारा अपनों से बिछड़ने का शोक व्यक्त करने के तरीकों का वर्णन किया है जिसमें हाथी द्वारा भावनाएं प्रकट करने का तरीका अचरज भरा था।

किताब के जरिए उन्होंने बताया कि एक शोधकर्ता द्वारा हाथी के शव को रेत में छोड़ दिये जाने पर पाया गया कि हाथियों के पांच अलग-अलग परिवार उस हाथी के शव के पास आए और सभी ने अलग-अलग तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। किसी ने शव के चारों ओर चक्कर लगाकर दु:ख व्यक्त किया... किसी ने चुपचाप उसके पास खड़े रहकर तो किसी ने मरे हुए हाथी की हड्डियां अपनी सूंड से उठाकर अपनी संवेदना प्रकट की। बारबरा का कहना है कि वे यह नहीं मानतीं कि जानवरों का शोक प्रकट करने का तरीका इंसानों की तरह का है किन्तु कुछ प्रजातियों में दु:ख व्यक्त करने की भावनाएं वास्तविक होती हैं। बारबरा के मुताबिक उन्होंने दो ऐसी बिल्लियों का भी अध्ययन किया जो बहनें थी और एक के मर जाने पर दूसरे ने लम्बे समय तक उसके शव को नहीं छोड़ा। हालांकि वह यह नहीं मानती कि जानवर भी इंसानों की तरह ही शोक व्यक्त करते हैं।

जानवरों में सबसे ज्यादा भावुक कौन

अक्सर जब हम किसी अपने से मिलते या बिछड़ते हैं तो भावुक हो जाते हैं। अगर कोई मित्र बहुत दिनों बाद मिले तो हम उसे खुशी से गले लगा लेते हैं। पर यदि कोई अपना बिछड़ जाए तो रोते-बिलखते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों में भावुकता पाई जाती है या नहीं? क्या कुत्ते-बिल्ली भी भावनाओं में बहते हैं? बड़े से हाथी और छोटी सी चींटी भी भावुक होते हैं? हाल ही में अमेरिका के विलियम एंड मेरी कॉलेज में मानव विज्ञान की प्रोफेसर, बारबरा जे किंग ने इस विषय पर पड़ताल की। जिसका जिक्र उन्होंने अपनी नई किताब 'हाउ एनीमल्स ग्रीव' किया है। बारबरा के अनुसार वैसे तो सभी जानवरों में भावुकता होती है। पर विशालकाय हाथी दुख व्यक्त करने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा भावुक होते हैं। जब एक हाथी के एक शव को रेत में छोड़ दिया गया, तो हाथियों के पाँच अलग-अलग परिवार उस हाथी के शव के पास आए और उन्होंने अलग-अलग तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। किसी ने हाथी के शव के चारों ओर घूमकर, तो किसी ने मरे हुए हाथी की हड्डियां अपनी सूंड़ पर उठाकर दुख व्यक्त किया।

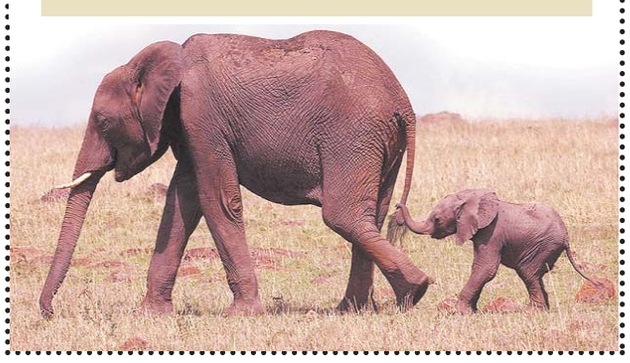

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सूरत में दस्तक नए स्ट्रेन के लक्षण

कोरोना के नए स्ट्रेन की सूरत में दस्तक, एक व्यक्तिमें नए स्ट्रेन के लक्षण की पुष्टि

क्रांति समय दैनिक

सूरत ,शहर समेत गुजरातभर में बड़ी मुश्किल से काबू में आया कोरोना संक्रमण फिर एक बार तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक से सूरतवासियों में चिंता बढ़ गई है। फरवरी महीने में ब्रिटेन से आए तीन लोगों के सैम्पल पूणे की लैब में भेजे गए थे। जिसमें एक व्यक्तिमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. आशीष नाइक ने ब्रिटेन से आए तीन लोगों के सैम्पल फरवरी महीने में पूणे की लैब भेजे गए थे। जिसमें एक व्यक्तिमें ब्रिटेन का नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। ऐहतियात के तौर पर सूरत के वराछा और रांदेर जोन में 530 घरों के 2000 लोगों को कोरन्टाइन किया गया है। साथ ही पालनपुर, पाल, वराछा और सरथाणा में भी ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं। गौरतलब है यह

नया स्ट्रे न आसानी से फैलता है। वायरस विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि ऐसा सच में है या नहीं।

इससे वैक्सीरन के लिए चिंता की कोई बात है या और गंभीर बीमारी फैलने का खतरा, यह भी क्लियर नहीं।

जैसे-जैसे आबादी में कोई वायरस फैलता है, वह अपना रूप बदलता जाता है।

कुछ ज्यादा तेजी से बदलते हैं, कुछ धीमे।

हाईकोर्ट से हार्दिक पटेल को बड़ी राहत
गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी

अहमदाबाद, गुजरात हाईकोर्ट से प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी प्रमुख हार्दिक पटेल को आज बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राजनीतिक कार्यों के लिए हार्दिक पटेल को गुजरात से बाहर जाने की आज मंजूरी प्रदान कर दी। राजद्रोह केस का सामना कर रहे हार्दिक पटेल को गुजरात नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत मिली थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने राजनीतिक कार्यों से अन्य राज्यों में आने-जाने की छूट देने की सत्र न्यायालय से मांग की थी। उस वक्तसत्र न्यायालय ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की मांग ठुकरा दी थी। राज्य सरकार ने हार्दिक पटेल की मांग का कड़ा विरोध किया था। सरकारी वकील ने कहा कि हार्दिक पटेल के खिलाफ गंभीर

मामले चल रहे हैं इसलिए उन्हें गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। सेशन्स कोर्ट के फैसले को हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने आज सेशन्स कोर्ट के फैसले को पलटते हुए हार्दिक पटेल को गुजरात से बाहर जाने की मंजूरी प्रदान कर दी।

गुजरात में कोरोना की रफ्तार हुई तेज, शनिवार को 571 नए मरीज सामने आए

क्रांति समय दैनिक

अहमदाबाद,गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और रोजाना औसत 45-50 नए केसों की वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना का आंकड़ा 500 को पार कर 515 पर पहुंच गया था, जो शनिवार को बढ़कर 600 के करीब पहुंच गया है। आज राज्य में कोरोना के 571 नए मरीज सामने आए हैं और 403 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। नवंबर महीने में राज्य में दिवाली त्यौहारों में लोगों की लापरवाही से कोरोना संक्रमण फैला था और इसका ग्राफ 1500 को पार कर गया था। जिसकी रोकथाम के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया था, जो अब तक जारी है। फरवरी महीने में कोरोना के रोजाना केसों की संख्या घटकर 250 के नीचे पहुंच गई थी। लेकिन फरवरी में स्थानीय चुनावों को लेकर रैली-रैला ने कोरोना रोकथाम के सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया है और लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में 123, सूरत कॉर्पोरेशन में 120, वडोदरा कॉर्पोरेशन में 104, राजकोट कॉर्पोरेशन में 51, सूरत में 14, वडोदरा में 13, कच्छ में 12, आणंद में 11, जामनगर कॉर्पोरेशन और मेहसाणा में 9-9, भावनगर कॉर्पोरेशन और साबरकांठा में 8-8, गिर सोमनाथ, महीसागर और राजकोट में 7-7, गांधीनगर, गांधीनगर

क्रांति समय फाउंडेशन (NGO)

कॉर्पोरेशन और खेडा में 6-6, जूनागढ़, नर्मदा और पंचमहल में 5-5 समेत राज्यभर में कुल 571 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। जबकि 403 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट गए। शनिवार को राज्य के पोरबंदर, सुरेन्द्रनगर और वलसाड समेत तीन जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। राज्य में कोरोना से अब तक कुल 265372 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। शनिवार को अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में एक मरीज की मौत के साथ ही राज्य में अब तक 4414 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 3025 सक्रिय मरीजों में 2980 स्टेबल हैं और 45 मरीज वेन्टीलेटर पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 1374244 लोगों की कोरोना का पहला और 330463 लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु और 45 से 60 साल की उम्र के गंभीर रोगों के मरीजों समेत कुल 131821 लोगों को पहला लगाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की गलतियों का उल्लेख होना चाहिए : कांग्रेस

क्रांति समय दैनिक

अहमदाबाद,गुजरात कांग्रेस प्रमुख और आंकलाव से विधायक अमित चावड़ा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्तकिए।

अमित चावड़ा ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे मांग की थी कि वे विधानसभा में तटस्थ और दलगत राजनीति से परे होकर अभिभाषण दें। ताकि सभी लोग दलगत राजनीति त्याग राज्यपाल के अभिभाषण से अच्छे विचार लेकर आगे बढ़ें।

अमित चावड़ा ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण को कांग्रेस के सभी विधायकों ने पूरे ध्यान से सुना। स्वाभाविक है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की प्रशंसा, उपलब्धि और योजनाएं की बातें होती हैं। यदि इसमें जनता की वास्तविक समस्या, वेदना, दर्द इत्यादि का भी उल्लेख कर सच्चाई फ्लोर पर रखी जाती, सरकार की गलतियों के लिए भले ही फटकार नहीं लगाते परंतु हिदायत देते हुए उसे आईना दिखाया होता तो अभिभाषण का हम स्वागत करते। चावडा ने कहा कि गुजरात में कोरोना महामारी से चार हजार लोगों की मौत, लोगों की मुश्किलें, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में 200 से अधिक की मौत, महंगाई से जूझ रहीं गृहणियां, महंगी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगार संघर्षरत युवक, मंदी की मार और आर्थिक रूप से बर्बात गुजरात के छोटे-मोटे व्यापारी, फिक्स वेतन कोन्ट्रेक्ट-आउटसोर्स की प्रथा के कारण राज्य के शोषित युवक इत्यादि का राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया जाना दुख की बात है। गुजरात में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पिछले दो साल में 200 करोड़ से अधिक की शराब और नशीले पदार्थ गुजरात से पकड़े गए हैं, जो राज्य की युवापीढ़ी के नशे की आदी होने का इशारा करते हैं।

पुलिस और प्रशासन सामान्य लोगों को जिस प्रकार जुर्माना वसूल कर उन्हें परेशान कर रही है, उसका भी अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

सार-समाचार

राज्य की झुग्गी बस्तियों में भी ''नल से मिलेगा जल'' : मुख्यमंत्री

गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज विधानसभा में राज्य की झुग्गी बस्तियों में ''नल से जल'' उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि 2022 तक राज्य का एक भी घर इस योजना से वंचित नहीं रहेगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आदिवासी परिवारों को स्वजलधारा और सेक्टर रिफॉर्म योजना के बारे में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशभर में नल से जल योजना के तहत घर-घर नल से पानी उपलब्ध कराने की घोषणा कर समूचे देश को पानीजनित रोगों से मुक्त कराने का संकल्प किया है। वर्ष 2024 तक देशभर में नल से जल योजना के तहत घर घर पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। गुजरात में यह योजना 2022 तक पूरी करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत राज्य की झुग्गी बस्तियों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौराष्ट्र में क्षारयुक्त पानी की वजह से पथरी, उत्तरी गुजरात में क्लोराइडयुक्त पानी के कारण हाथीपग या दांत पीले होने जैसे रोगों से लोगों को जूझना पड़ा है। समूचे राज्य को 100 प्रतिशत फिल्टर्ड पानी उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार प्रयत्नशील है और इसके तहत नल से जल योजना का कार्य तेज किया गया है। विजय रूपाणी ने बताया कि इस योजना का आज तक राज्य में 82 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जबकि 18 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र में काम चल रहा है। आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों में लिफ्ट इरीगेशन के जरिए नल से जल योजना नेटवर्क पूर्ण करने का काम चल रहा है, जो अगले 17 महीनों में पूरा करने का सरकार का लक्ष्य है। अर्थात 2022 तक राज्य का एक भी घर नल से जल योजना से वंचित नहीं रहेगा।

जलापूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने अरवल्ली और साबरकांठा जिले में स्वजलधारा और सेक्टर रिफॉर्म योजना के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य का एक भी गांव शुद्ध पेयजल से वंचित न रहे इसकी सरकार ने पहल की है। साबरकांठा जिले में आदिवासी परिवारों को स्वजलधारा और सेक्टर रिफॉर्म योजना के तहत खेडब्रह्मा के 18, विजयनगर के 5, हिम्मतनगर के 7 और ईडर के 3 गांवों में 100 प्रतिशत घरों को नल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि अरवल्ली जिले के भिलोडा में 38 और मेघरज के 29 गांवों के घरों को नल से जल उपलब्ध हो रहा है। इतना ही नहीं वर्ष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी गांवों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराने को सरकार कटिबद्ध है।

राज्य के 82 फीसदी नागरिकों को विभिन्न योजनाओं से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति : उप मुख्यमंत्री

गांधीनगर, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज बताया कि राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल जलापूर्ति करने के लिए सरकार ने दृढ़ निश्चय और समयबद्ध आयोजन किया है। जिसकी वजह से आज राज्य के 82 फीसदी नागरिकों को विभिन्न योजनाएं के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि नल से जल योजना के तहत राज्य के राजस्व गांवों को शामिल करने के बाद गांवों के खेतों में छुटपुट क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को भी इसका लाभ देने का आयोजन है।

अहमदाबाद होकर गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

अहमदाबाद, पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद होकर गुजरने वाली 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में अस्थाई रूपसे अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. ट्रेन संख्या 02945 मुंबई सेंट्रल - ओखा स्पेशल में 08 मार्च 2021 से 14 मार्च 2021 तक तथा ट्रेन संख्या 02946 ओखा - मुंबई सेंट्रल स्पेशल में 10 मार्च 2021 से 16 मार्च 2021 तक एक स्लीपर कोच अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

2. ट्रेन संख्या 09027 बांद्रा टर्मिनस - जम्मूतवी स्पेशल में 13 मार्च 2021 से तथा ट्रेन संख्या 09028 जम्मूतवी - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल में 15 मार्च 2021 से एक स्लीपर कोच अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

3. ट्रेन संख्या 02949 बांद्रा टर्मिनस -दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल में 10 मार्च 2021 से तथा ट्रेन संख्या 02950 दिल्ली सराय रोहिल्ला - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल में 11 मार्च 2021 से एक स्लीपर कोच अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

4. ट्रेन संख्या 02965 बांद्रा टर्मिनस - भगत की कोठी स्पेशल में 12 मार्च 2021 से तथा ट्रेन संख्या 02966 भगत की कोठी - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल में 13 मार्च 2021 से एक स्लीपर कोच अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

हिमाचल कांग्रेस ने राज्य के बजट को दिशाहीन करार दिया, कहा- सरकार बढ़ती महंगाई से नहीं दिला पाई निजात

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किये गए राज्य के बजट को दिशाहीन करार देते हुए कहा कि सरकार लोगों को बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने में नाकाम रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधानसभा में पेश किया गया बजट अधूरा दस्तावेज है, जिसमें राज्य की जनता से झूठे वादे किये गए हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने विधानसभा में जो बजट घाटा पेश किया है, उसमें राज्य के कुल कर्ज और वित्तपोषण के बीच अंतराल का कोई जिक्र नहीं हैं। ठाकुर ने शनिवार को विधानसभा में चौथी बार बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 50,192 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो कोविड-19 संकट के बावजूद पिछले बजट से 1,061 करोड़ रुपये अधिक है। अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही कर-रहित बजट पेश करने का दावा कर रहे हों लेकिन इस बात की संभावना भी है कि सरकार वित्तीय घाटे से निपटने के लिये साल के बीच में कर लगा दे। उन्होंने कहा, राज्य की विकास दर नकारात्मक रही है लेकिन मुख्यमंत्री ने पुरानी योजनाओं को नए कलेवर में पेश करके जनता को लुभाने का प्रयास किया है।बजट दिशाहीन और अधूरा दस्तावेज है।

केंद्र सरकार पर बरसे दिग्विजय सिंह, बोले- भाजपा ईवीएम पर निर्भर है

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को कहा कि नए कृषि कानूनों और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर जनता की नाराजगी को लेकर केन्द्र सरकार परेशान नहीं है क्योंकि भगवा पार्टी को चुनाव जीतने के लिये ईवीएम पर भरोसा है। केन्द्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर दिग्विजय अपनी बाजू पर काली पट्टी बांध कर शाजापुर जिले के जयहेड़ा में संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। उन्होंने कहा, '' नवंबर माह में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपये थी, जो अब बढ़कर 890 रुपये हो गयी है। केन्द्र सरकार की उज्जवला योजना के 80 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी इसे खरीदने में असमर्थ हैं।'' मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासन में पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुक्ल 10 गुना तक बढ़ गया है। इससे मंहगाई में वृद्धि हुई है और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच नाराजगी देखकर नेता चिंतित हो जाते हैं, लेकिन भाजपा इससे प्रभावित नहीं है क्योंकि वह ईवीएम पर निर्भर है।

गृहमंत्री अमित शाह रविवार को तमिलनाडु और केरल के राजनीतिक दौरे पर जाएंगे

नयी दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह रविवार को तमिलनाडु और केरल के एकदिवसीय राजनीतिक दौरे पर जाएंगे, जहां वह घर-घर प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि शाह तिरूवनंतपुरम में भाजपा की ''केरल विजय यात्रा'' के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह दोनों राज्यों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कन्याकुमारी के सुचिंद्रम में ''वेटरी कोडी एनाधी'' (चुनावी जीत के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम) की शुरुआत करने के अलावा शाह वहां एक रोडशो भी करेंगे, जहां कांग्रेस के निवर्तमान सांसद की मौत के कारण खाली हुई सीट पर भाजपा लोकसभा उपचुनाव भी लड़ रही है। भाजपा सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के साथ मिलकर राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रही है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में छह अप्रैल को एक चरण में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई असम के शिवसागर से लड़ेंगे चुनाव

गुवाहाटी। जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई असम विधानसभा चुनाव में अपनी नवगठित पार्टी राइजर दल के उम्मीदवार के तौर पर शिवसागर सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए राइजर दल के कार्यकारी अध्यक्ष भास्को डी सैकिया ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष गोगोई शिवसागर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण में राइजर दल 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि, एक सीट पर उसकी ओर से अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना बाकी है। वहीं, दूसरे चरण में छह सीटों पर किस्मत आजमाएगी।

अब महाराष्ट्र से एमपी आने वाले लोगों के लिए जरूरी होगा कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिये कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये आधिकारिक बयान में बताया गया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिये हैं। समीक्षा बैठक में चौहान ने कहा, '' भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैन और महाराष्ट्र से लगे जिलों में कोरोना से प्रभावित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है।

अदालतों में मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता : राष्ट्रपति कोविंद

जबलपुर। (एजेंसी)।

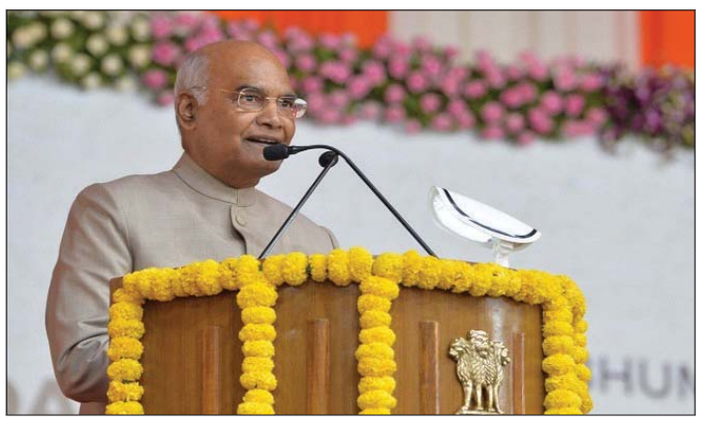

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए जिला अदालतों के न्यायाधीशों के साथ-साथ अर्द्ध-न्यायिक कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत पर शनिवार को जोर दिया। राष्ट्रपति ने यहां अखिल भारतीय राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, ''अब जरूरत है कि देश की अदालतों, विशेष रूप से जिला अदालतों में लंबित मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण करने के लिए न्यायाधीशों के साथ-साथ अन्य न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया जाए।''

उन्होंने कहा, ''इनके बीच, ज्ञान एवं सूचना के आदान-प्रदान के लिए ऐसे सम्मेलनों के अलावा, कोई अन्य स्थायी मंच स्थापित किया जा सकता है। इससे, एक ओर जहां मुकदमों के निस्तारण में तेजी आ सकती है, वहीं न्यायिक प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में अखिल भारतीय परिदृश्य का भी विकास हो सकता है।'' सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी (एमपीएसजेए) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। कोविंद ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए एमपीएसजेए के प्रयासों की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने न्यायिक प्रणाली में तकनीक के उपयोग में वृद्धि का भी स्वागत करते हुए कहा कि देश में 18,000 अदालतों का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग 76 लाख मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालतों में की गई।'' कोविंद ने कहा, ''अब ई-अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ई-कार्यवाही, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केन्द्रों की सहायता से जहां न्याय-प्रशासन की सुगमता बढ़ी है, वहीं कागज के इस्तेमाल में कमी आने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव हुआ है।''

उन्होंने कहा, '' कुछ उच्च न्यायालय भी स्थानीय में अदालती फैसलों का अनुवाद कराने लगे हैं। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन अब मेरी अपेक्षाएं कुछ और बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूं कि सभी उच्च न्यायालय, अपने-अपने प्रदेश की अधिकृत में, जन-जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद, उच्चतम न्यायलय की तरह एक ही समय पर उपलब्ध व प्रकाशित कराएं। राष्ट्रपति ने उनके सुझाव पर शीर्ष अदालत द्वारा इस दिशा में कार्य करते हुए न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद नौ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की प्रशंसा की। राष्ट्रपति शनिवार से मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं।

योगी आदित्यनाथ ने रामायण की विभिन्न घटनाओं का किया जिक्र, बोले- इसमें विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए शनिवार को कहा कि इस महाकाव्य में विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय है। मुख्यमंत्री शनिवार को यहां संत गाडगे सभागार में रामायण विश्व महाकोश (ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण) की 'कर्टेन रेजर' पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किया था। उन्होंने कहा,'' यह पुस्तक हमें विज्ञान और आध्यात्म के अनछुए पहलुओं से परिचित कराएगा।''

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 'रामायण विश्व महाकोश' को ई-बुक के रूप में भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान रामायण विश्व महाकोश पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम की संस्कृति पहली संस्कृति है, जिसने वैश्विक मंच पर अपना स्थान बनाया। इसके हजारों वर्ष बाद भगवान बुद्ध की संस्कृति वैश्विक मंच पर स्थापित हुई।

किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे, प्रदर्शनकारी किसानों ने एक्सप्रेस-वे पर आवागमन रोका

चंडीगढ़। (एजेंसी)।

केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली की सीमा पर अपने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को हरियाणा में छह लेन वाले कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर कुछ स्थानों पर यातायात अवरुद्ध कर दिया। किसानों का प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो अपराह्न चार बजे तक जारी रहा। काले झंडे थामे तथा बांह पर काली पट्टी बांधे किसानों और काला दुपट्टा पहने महिला प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे नहीं माने जाने को लेकर भाजपा नीत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोनीपत तथा झज्जर और कुछ अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली तथा अन्य वाहन लेकर आए और उन्हें केएमपी एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में बीच में खड़ा कर दिया।

हरियाणा पुलिस ने यातायात का मार्ग बदलने के लिये प्रबंध कर रखा था। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक्सप्रेस-वे पर यातायात अवरूद्ध करने का आह्वान किया था। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे 136 किलोमीटर लंबा है। मानेसर-पलवल खंड 53 किलोमीटर लंबा है और इसका उद्घाटन 2016 में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था, वहीं 83 किलोमीटर लंबे कुंडली-मानेसर खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में किया था। भारतीय किसान यूनियन (दाकुंडा) के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा, '' हम केएमपी एक्सप्रेस-वे पर यातायात अवरुद्ध करेंगे लेकिन आपात सेवा में लगे वाहनों को जाने दिया जाएगा।''

सोनीपत में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, '' तीनों कृषि कानूनों को वापस लिये जाने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे।'' किसानों ने पलवल जिले में भी प्रदर्शन किया। केएमपी एक्सप्रेस-वे दिल्ली की हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़कों पर भीड़ को कम करने खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में आने वालों ट्रकों की संख्या को कम करने के लिए बनाया गया था। इससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिली। गौरतलब है कि हजारों की संख्या में किसान केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले वर्ष नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों की आशंका है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और उन्हें बड़े कॉर्पोरेट घरानों के 'रहमोकरम' पर छोड़ देंगे। हालांकि, सरकार का कहना है कि नए कानून किसानों के लिए बेहतर अवसर लाएंगे और इससे कृषि के क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी भी आएगी।

बंगाल चुनाव : भाजपा ने 57 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे चुनाव

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 57 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसके अनुसार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अशोक डिंडा और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष भी भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने वालों में शामिल हैं।

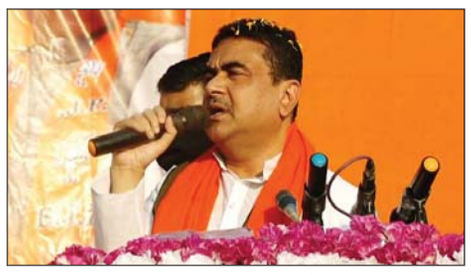

उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक सीट अपने सहयोगी दल एजेएसयू को दी है। इसके साथ ही पार्टी ने 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में होने वाले चुनाव के पहले दो चरणों के लिए 60 में से तीन को छोड़कर बाकी सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सिंह ने कहा कि राज्य में ÷जंगल राज÷ की स्थिति है और मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस को हराकर भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड़ परेड मैदान में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद उनकी यह पहली रैली होगी। नंदीग्राम में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन ने 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया था। नंदीग्राम में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी और अब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अधिकारी 2016 में इस सीट से विजयी हुए थे और हाल में भगवा पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली का भी अपना शिक्षा बोर्ड होगा

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब अलग से दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये बोर्ड तीन लक्ष्य पूरे करेगा। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो आने वाले समय में हर क्षेत्र में देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हों। हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनें और ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस को हम स्कूलों और बोर्ड में लेकर आएंगे। इस साल 20-25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि 4-5 साल में स्वेच्छा से सारे सरकारी, निजी स्कूल बोर्ड में शामिल हो जाएंगे।

इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि दिल्ली में आखिर अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि छह साल पहले हमने बजट का 25 फीसदी पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करना चालू किया। इससे सरकारी स्कूलों की इमारत अच्छी बनने लगी, लैब्स बनने लगे, साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था हुई इत्यादि। उन्होंने कहा कि हीन भावना से ग्रसित सरकारी स्कूलों का ढांचा बदला गया। हमने दूसरा परिवर्तन किया कि शिक्षकों और प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग के लिए अच्छी जगह भेजा। उन्हें कैम्ब्रिज में प्रिशिक्षण दिया गया।

बेगूसराय में गरजे गिरिराज, बोले- अगर अधिकारी नहीं सुनता है तो बांस उठाकर मारो !

पटना। (एजेंसी)।

भाजपा के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बार गिरिराज सिंह ने अधिकारियों जमकर क्लास लगाई। बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है तो उसकी बांस उठाकर पिटाई करिए।

भाजपा नेता ने जनता से कहा कि आप मालिक हैं लोकतंत्र में, सांसद, एमएलए, पीएम, एसडीओ, ज्यूडिशरी ये आपके अधीन है। आप अपनी अच्छी बात लेकर के जाएं। एक मित्र ने लिखकर दिया कि सीओ गड़बड़ी कर रहा है। आप जाइये, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यह आपका अधिकार है और अगर आपके अधिकार का हनन होता है तो गिरिराज आपके साथ खड़ा हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि आपने मुझे सांसद बनाया है। आपने किसी को जिलापरिषद बनाया है। आपके बल पर कोई मुखिया बनाया है। मुखिया, एमएलए, एमपी के बल पर आप नहीं हैं। यह ध्यान में रखिए और मनोबल को ऊंचा रखिए। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कोई सुनता नहीं है तो दोनों हाथ से बांस से मारो न। ये शब्द हम नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनता है।

अमित शाह और राजनाथ सिंह हैं किसान लेकिन कृषि मंत्री तोमर नहीं ! 538 में 216 सांसदों का दस्तावेजों में जिक्र

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने संसद के करीब पार्क में खेती करने की बात कही है। जबकि सरकार का कहना है कि नए कानून कृषि सुधारों की दिशा में अभूतपूर्व कदम हैं। इससे किसानों को लाभ होगा। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। जो यह दर्शाती है कि देशवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने सांसद किसान है।

हिन्दी न्यूज वेबसाइट %दैनिक भास्कर% की एक रिपोर्ट के मुताबिक 538 सांसदों में से 216 सांसद किसान हैं। दरअसल, बजट सत्र 2021-22 के दौरान संसद में कृषि कानूनों के विषय पर जमकर हो-हल्ला हुआ। अधिकतर विपक्षी सांसद इसके विरोध में तो कुछ ही इसके समर्थन में दिखाई दिए। यहां तक की पहले कृषि कानूनों को समर्थन करने वाले कुछ सांसदों ने विरोध प्रदर्शन को बड़ा होता देख, अपना नजरिया बदला और इसका विरोध करने लगे। इस बार के सत्र में तो कई नेताओं ने यहां तक कहा कि वह भी किसान हैं और वह इनका दर्द जानते हैं। इसी आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें दावा किया गया कि संसद की 5 खाली सीटों को छोड़ दिया जाए तो 538 में से 216 सांसदों ने सरकारी दस्तावेजों में खुद को किसान बताया है।

किस पार्टी के पास कितने किसान ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के पास 302 सांसदों में से 139 किसान सांसद हैं। जबकि कांग्रेस के पास 51 में से 13, द्रमुक के पास 24 में से 10, तृणमूल कांग्रेस के 22 में से 1, वाईएसआर कांग्रेस के 21 में से 6, शिवसेना के पास 18 में से 11, जदयू के 16 में से 7, बीजद के 12 में से 2, बसपा के 10 में से 5, टीआरएस के 9 में से 5, लोजपा के 6 में से 4 इत्यादि किसान सांसद हैं।

रिपोर्ट्स में किसानों और किसान सांसदों के महीनेभर की आय का भी उल्लेख किया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नाबार्ड (हवाला) के आंकड़ों के मुताबिक हिन्दुस्तान का किसान महीने में औसतन 8,931 रुपए कमाता है। जबकि सांसदों को सभी सुविधाओं के बावजूद हर माह 2 लाख 30 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। अगर हम कोरोना महामारी की वजह से सांसदों की घटी तनख्वाह की बात करें तो अभी उन्हें 1 लाख 73 हजार रुपए मिलता है। हालांकि, सबकुछ सही रहा तो कुछ वक्त बाद सांसदों को वापस से पुरानी तनख्वाह मिलने लगेगी।

मोदी कैबिनेट में कितने किसान सांसद ?

इस रिपोर्ट की सबसे चौंका देने वाली बात तो यह रही कि मोदी सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान सांसद नहीं हैं। जबकि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई किसान सांसद हैं। मोदी सरकार में कुल 21 केंद्रीय मंत्री और 32 राज्यमंत्री हैं। ऐसे में 21 केंद्रीय मंत्रियों में 7 और 32 राज्यमंत्रियों में 13 किसान हैं।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)